वर्ष 13 ● अंक 45 ● 8 पृष्ठ ● मूल्य 5 रुपये

सोमवार 13 अप्रैल 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 7

आलू का भंडारण इस साल 15 फीसदी कम

विवेक गंभीर ▸▸ पृष्ठ 2

छोटे और बड़े दोनों पैक के लिए बढ़ेगी मांग

एक नजर

कोरोना से जुड़े घटनाक्रम से तय होगी बाजार की चाल

शेयर बाजारों की दिशा इस सप्ताह कोविड-19 से जुड़े घटनाक्रम से तय होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कम कारोबारी सत्र वाले सप्ताह के दौरान बाजार में काफी हद तक उतार-चढ़ाव रहेगा। अंबेडकर जयंती पर मंगलवार को बाजार बंद रहेंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि यदि देश में लागू लॉकडाउन को आंशिक रूप से हटाया जाता है और आर्थिक गतिविधियां शुरू होती हैं तो बाजार की धारणा कुछ सुधर सकती है। जानकारों का कहना है कि बाजार में आई हालिया तेजी कुछ समय के लिए है और संभवत: अधिक टिकने वाली नहीं है। बाजार इस वायरस से संबंधित खबरों और लॉकडाउन में किसी तरह की ढील आदि की खबरों से ऊपर-नीचे होगा। इस हफ्ते सोमवार को मुद्रास्फीति दर और मंगलवार को थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े आएंगे, जिस पर निवेशकों की नजर रहेगी।

विश्व बैंक का 1.3 से 2.8 फीसदी वृद्धि दर का अनुमान

विश्व बैंक ने कहा है कि कोरोनावायरस महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका दिया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन 1991 के उदारीकरण के बाद सबसे खराब रहेगा। विश्व बैंक ने रविवार को दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 1.5 से 2.8 फीसदी के बीच रहेगी। रिपोर्ट में कहा है कि 2019-20 में भारतीय अथव्यवस्था की वृद्धि दर 4.8 से 5 फीसदी के बीच रहेगी। इससे पहले एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 4 फीसदी प्रतिशत किया है। एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 3.5 फीसदी कर दिया है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है।

दो जीवन बीमा फर्मों में हिस्सा बनाए रखेगा पीएनबी

पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) दो जीवन बीमा उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखेगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण से बैंक को इसकी मंजूरी मिल गई है। 1 अप्रैल ओरियंटल बैंक कॉमर्स (ओबीसी) के पीएनबी में विलय के बाद ओबीसी की केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफमें 23 फीसदी हिस्सेदारी पीएनबी को हस्तांतरित हो गई है। पीएनबी पहले से यानी 2012 से पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस का प्रवर्तक हैं। इसमें उसकी 30 फीसदी हिस्सेदारी है। पीएनबी के प्रबंध निदेशक एस एस मल्लिकार्जुन राव ने दो बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अभी बाहर निकलने की कोई अनिवार्यता नहीं है। हमने इस बारे में इरडा से बात है। समय आने पर हम इस पर निर्णय करेंगे।

बोरिस जॉनसन को मिली अस्पताल से छुट्टी

कोरोनावायरस से संक्रमित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जॉनसन ने जान बचाने के लिए राज्य वित्त पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों और कर्मियों को धन्यवाद दिया। इस बीच डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा है कि जॉनसन लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल से प्रधानमंत्री आवास आ गए हैं। हालांकि चिकित्सकों की सलाह के अनुसार वह तत्काल कामकाज नहीं संभालेंगे। उनके काम पर लौटने की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री को पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ समय की जरूरत है।

डॉलर अदला-बदली की लागत ऐतिहासिक ऊंचाई पर

कोरोनावायरस महामारी से उत्पन्न हालात में वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष धन की समस्या खड़ी होने का खतरा दिख रहा है। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर स्वैप (अदला-बदली) का प्रमिमय या ब्याज इस समय ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। बासेल स्थित बैंक ऑफ इंटरनैश्नल सेटलमेंट ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।

आज का सवाल

क्या सीमित दायरे में देनी चाहिए लॉकडाउन से छूट

www.bshindi.com पर राय भेजें। आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो BSPY और यदि न है तो BSPN लिखकर 57007 पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या सरकार को बढ़ानी चाहिए लॉकडाउन की अवधि	हां	75.00%
	नहीं	25.00%

लॉकडाउन में ढील की कवायद!

कृषि कार्यों एवं सीमित इलाकों में सेवाओं को अनुमति संभव

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली/लखनऊ, 12 अप्रैल

लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से औपचारिक घोषणा के इंतजार के बीच तेलंगाना 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। देशव्यापी लॉकडाउन की समयसीमा मंगलवार को समाप्त हो रही है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 से 273 लोगों की मौत हो गई है और इसके कुल मामलों की संख्या आज 8,356 पहुंच गई। इस बीच वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर सकते हैं। केंद्र सरकार ऐसे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना चाहती है जहां कोविड-19 के मामले कम हैं।

कुछ राज्यों ने दिखाया है कि कैसे आंशिक लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मामलों की स्थिति के मुताबिक विभिन्न इलाकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अधिक प्रभावित क्षेत्रों को पहले ही रेड जोन घोषित किया जा चुका है और ऑरेंज जोन में ऐसे इलाकों को रखा गया है जहां अधिक खतरा है।

- तेलंगाना में 30 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन
- दिल्ली ने इलाकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणियों में बांटने का काम शुरू किया
- केंद्र सुरक्षित इलाकों में सीमित सेवाओं को दे सकता है अनुमति
- कृषि गतिविधियों को दी जा सकती है अनुमति
- उत्तर प्रदेश नें 5,281 औद्योगिक इकाइयों को खोला
- आजादपुर मंडी में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सम-विषम योजना

देशव्यापी लॉकडाउन को 14 अप्रैल से आगे बढ़ाने के बारे में अभी काम चल रहा है लेकिन एक सुझाव यह भी आया है कि 15 से अधिक मामलों वाले इलाके को रेड जोन और इससे कम मामले वाले इलाकों को ऑरेंज जोन घोषित किया जाए। जहां कोई मामला नहीं है ऐसे इलाकों को ग्रीन जोन में रखा जाए।

सरकार समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी कृषि गतिविधियों को अनुमति देने पर विचार कर रही है। कुछ राज्यों जरूरी सामान बनाने वाले उद्योगों को भी काम शुरू करने की अनुमति देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में 5,281 औद्योगिक इकाइयों को फिर से खोलने में मदद की।

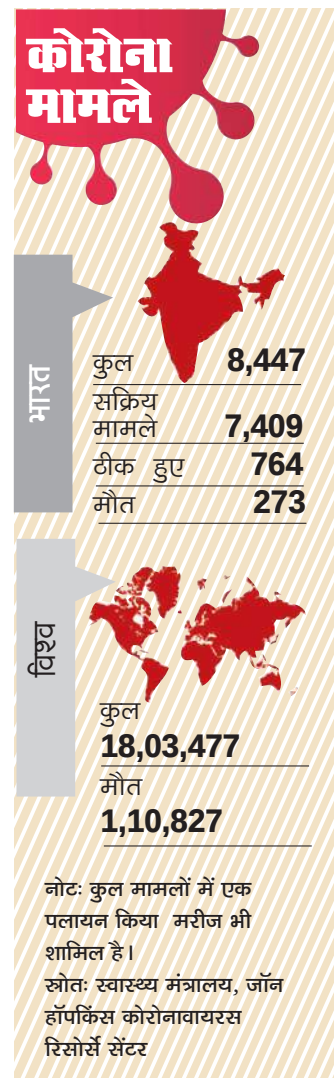

नोट: कुल मामलों में एक पलायन किया मरीज भी शामिल है।
स्रोत: स्वास्थ्य मंत्रालय, जॉन हॉपकिंस कोरोनावायरस रिसोर्स सेंटर

उत्तराधिकार नीति पर आरबीआई सख्त

रघु मोहन
मुंबई, 12 अप्रैल

- उम्मीदवारों के व्यावसायिक परिचालन और बोर्ड अनुभव पर किया जाएगा गौर
- नामांकन एवं पारितोषिक समिति का काम बढ़ना तय
- निजी बैंक के बोर्डों की बढ़ेगी भूमिका

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) निजी बैंकों के लिए उत्तराधिकार योजना की नीति को और सख्त बनाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी की पहचान करने और उन्हें अपनी नई भूमिका में ढलने का मौका देने के लिए अधिक कठोर समयसीमा लागू की जा सकती है। इस समय इन पदों पर बैठे व्यक्तियों की सेवा में विस्तार को इस बात से जोड़ा जा सकता है कि जिस बैंक के वे मुखिया हैं, उसमें उत्तराधिकार की योजना कितनी मजबूत है और उस पद के लिए लोगों को कैसे तैयार किया जा रहा है।

केंद्रीय बैंक इन पदों के लिए उम्मीदवारी पर विचार करते समय यह देख सकता है कि उन्होंने महत्वपूर्ण वाणिज्यिक परिचालनों को चलाने में कैसा प्रदर्शन किया है, निदेशक मंडल में उन्हें कितना अनुभव है और निदेशक मंडल के विचार-विमर्श में उनका कितना योगदान रहा है। ऐसे में बैंकों की नामांकन एवं पारितोषिक समिति की जिम्मेदारी बढ़ना तय है और निजी बैंकों के निदेशक मंडलों को भी उत्तराधिकार योजना में अधिक भागीदारी करनी होगी।

निजी बैंकों में उत्तराधिकार योजना की प्रक्रिया अभी ठीक ढंग से निर्धारित नहीं है और केंद्रीय बैंक चाहता है कि दूसरी पीढ़ी के हाथ में प्रबंधन की बागडोर सुगम तरीके से आए। साथ ही नियंत्रण से बाहर की घटनाओं के लिए आपात योजना में शामिल किए गए 'प्रमुख व्यक्तिगत जोखिम' में भी कमी की जाए। उत्तराधिकार योजना का मतलब है निजी बैंकों के शीर्ष प्रबंधन से परे देखना और मौजूदा मुखिया का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही दूसरी पंक्ति को पहचान लेना। अधितर निजी बैंकों में उप प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी तक नहीं हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ऊर्जित पटेल के समय में केंद्रीय बैंक ने उत्तराधिकार योजना का कठोर ढांचा तैयार करना शुरू किया था। अब पता चला है कि 'निजी बैंकों में पिछले एक साल में हुई घटनाओं के कारण यह मुद्दा एक बार फिर नियामकीय एजेंडे पर लौट आया है।'

इसका नमूना पिछले हफ्ते ही दिखा, जब रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक में अतिरिक्त निदेशक के तौर पर शशिधर जगदीशन और कार्यकारी निदेशक के पद पर भावेश जवेरी की नियुक्ति पर तब तक के लिए रोक लगा दी, जब तक बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी का उत्तराधिकारी तय नहीं कर दिया जाता। जगदीशन और जवेरी को बैंक के मुखिया पद का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 17 अप्रैल, 2014 को आदेश दिया था कि उत्तराधिकार की स्पष्ट योजना अनिवार्य है और यह निदेशकों का मुख्य कार्य होगा। निजी बैंकों के मामले में इस आदेश की जमकर आजमाइश हुई है और केंद्रीय बैंक को इस मोर्चे पर कड़ाई बरतने की जरूरत है।

आईसीआईसीआई बैंक से चंदा कोछड़, ऐक्सिस बैंक से शिखा शर्मा और येस बैंक से राणा कपूर की अलग-अलग वजहों से अचानक विदाई के कारण बैंकों के निदेशक मंडल मुश्किल में आ गए थे। इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी रोमेश सोबती के उत्तराधिकारियों की तलाश के कारण यह बात चर्चा में आ गई कि केंद्रीय बैंक निजी बैंकों के निदेशक मंडल सदस्यों की आयु सीमा कंपनी अधिनियम के मुताबिक 70 साल से बढ़ाकर 75 साल करेगा या नहीं। मौजूदा परिपाटी के मुताबिक निजी बैंक मौजूदा एमडी और सीईओ का कार्यकाल खत्म होने से चार महीने पहले तीन उम्मीदवारों की सूची मंजूरी के लिए केंद्रीय बैंक के पास भेजते हैं।

चीन के बैंक ने एचडीएफसी में बढ़ाया हिस्सा

समी मोडक और अभिजित लेले
मुंबई, 12 अप्रैल

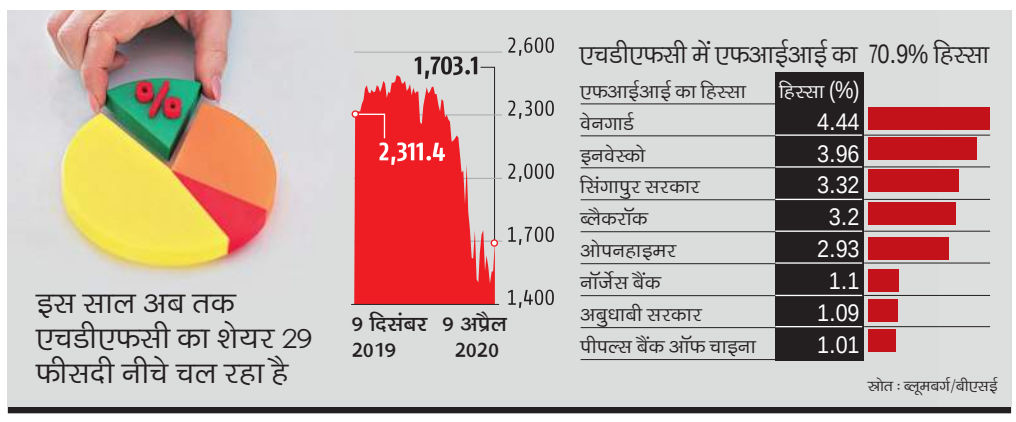

स्रोत : ब्लूमबर्ग/बीएसई

चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीसीओ) ने भारत के हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैंस कॉरपोरेशन (एचडीएफसी) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। एचडीएफसी के शेयर भाव में हाल में आई गिरावट का फायदा उठाते हुए पीबीसीओ ने अपना हिस्सा बढ़ाया है।

एचडीएफसी द्वारा किए गए नियामकीय खुलासे से पता चला है कि चीन के केंद्रीय बैंक के पास मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में 1.75 करोड़ यानी 1.01 फीसदी हिस्सेदारी थी। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा, 'उन्होंने चीन के सॉवरिन वेल्थ फंड की ओर से शेयर खरीदे हैं। जब चीन के केंद्रीय बैंक की हिस्सेदारी एक फीसदी से अधिक हो गई तब हमने इसकी जानकारी दी।'

एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और मुख्य कार्याधिकारी केकी मिस्त्री ने कहा, 'पीबीसीओ पिछले कुछ समय से एचडीएफसी में निवेशक है। मार्च 2019 में उसने 0.8 फीसदी हिस्सेदारी ली थी और अब मार्च 2020 में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर एक फीसदी से अधिक हो गई है।' उन्होंने कहा कि पीबीसीओ एचडीएफसी का निष्क्रिय निवेशक है। सूत्रों ने कहा कि संभव है कि पीबीसीओ ने मार्च में अपनी हिस्सेदारी 0.2 फीसदी बढ़ाई है क्योंकि उस समय बाजार में चौतरफा बिकवाली की वजह से एचडीएफसी का शेयर करीब 25 फीसदी नीचे आ गया था।

कुल मिलाकर दिसंबर 2019 तिमाही में एचडीएफसी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की हिस्सेदारी 72.75 फीसदी थी जो मार्च 2020 तिमाही में घटकर 70.88 फीसदी रह गई।

पिछले हफ्ते बाजार में तेजी आने से एचडीएफसी का शेयर भी 13.6 फीसदी चढ़कर 1,633 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि इसका शेयर अभी भी इस साल अब तक 29 फीसदी नीचे कारोबार कर रहा है। मौजूदा बाजार भाव के आधार पर एचडीएफसी का मूल्यांकन करीब 2.95 लाख करोड़ रुपये है। आवास ऋण प्रदाता होने के अलावा एचडीएफसी होल्डिंग कंपनी भी है और इसके पास समूह की फर्मों एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी म्युचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस आदि में भी हिस्सेदारी है।

रविवार को एचडीएफसी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा था। चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का तर्क था कि चीन शेयर बाजार में आई गिरावट का लाभ उठाकर भारत की ब्लूचिप कंपनियों में अपने शेयर खरीद रहा है। हालांकि विशेषज्ञों ने इसे खारिज करते हुए कहा कि शेयर की इस खरीद में कुछ भी असामान्य नहीं है।

वाहन उत्पादन केंद्र पर लॉकडाउन से पसरा सन्नाटा

अरिंदम मजूमदार
मानेसर/गुड़गांव, 12 अप्रैल

पवन कुमार को फैक्टरी से दूरी अब अखरने लगी है। 34 वर्षीय पवन प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे कंपनी से मिला लिबास पहन कर मानेसर में मारुति सुजूकी के संयंत्र में पहुंच जाते थे। पवन अकुशल कामगार हैं, इसलिए फैक्टरी में शारीरिक श्रम ही उन्हें मेहनताना दिलाता है। करीब 1 बजे उनके भोजन का समय होता था और इस दौरान वह करीब 30 मिनट कैंटीन में बिताते थे। शाम 5 बजे उनका काम खत्म हो जाता था और ओवरटाइम नहीं करने पर लगभग साढे पांच बजे तक वह अपने चॉल में पहुंच जाते थे। चॉल में पवन के साथ 4 और लोग रहते हैं।

कोरोनावायरस का प्रकोप शुरू होने के बाद 22 मार्च को देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजूकी ने अपने प्रमुख उत्पादन संयंत्र में उत्पादक कार्य रोक दिया। जब से उत्पादन कार्य बंद हुआ है तब से पवन काफी खालीपन महसूस करते हैं।

पवन कोई तकनीकी या यांत्रिक कौशल नहीं जानते हैं। द्वितीय स्तर पर अनुबंध पर काम करने वाले पवन कार उत्पादन में नहीं लगाए जा सकते हैं। आजीविका के लिए वह अपने शारीरिक श्रम पर ही निर्भर है, जिसके लिए उन्हें हरेक महीने महज 9,000 रुपये मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि मारुति ने मार्च के अंतिम आठ दिनों का उनका वेतन नहीं काटा है, लेकिन पवन को यह चिंता जरूर खाए जा रही है कि आखिर कंपनी आगे भी वेतन देती रहेगी या नहीं। वह कहते हैं, 'समय काटने के लिए मैं रोज आठ से नौ घंटे ताश खेलता हूं। मुझे ऐसी जिंदगी पसंद नहीं है। अगर फैक्टरी में कोई काम नहीं है तो हमारे जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं रह जाती है।'

संजय शर्मा

भारत के डेट्रॉयट माने जाने वाले मानेसर में लॉकडाउन की वजह से वाहन कंपनियों के संयंत्र बंद होने से वहां काम करने वाले मजदूरों को सता रहा रोजी-रोटी का संकट।

- छोटे कल-पुर्जे विनिर्माताओं का अस्तित्व संकट में
- लॉकडाउन के बाद ज्यादातर कामगार लौट गए हैं अपने घर
- मारुति, सुजूकी, हीरो, होंडा सहित कई बड़ी कंपनियों के उत्पादन संयंत्र हैं इस क्षेत्र में
- लॉकडाउन वाहन एवं संबद्ध क्षेत्र की रफ्तार पर लगा सकता है ब्रेक

राजस्थान के नीमराना तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला गुड़गांव-मानेसर-बावल का इलाका देश के सबसे बड़े वाहन उत्पादन केंद्र का ठिकाना है। किसी भी कार्य दिवस के दिन यहां काफी चहल-पहल देखने को मिलती है। फैक्टरियों में एक से बढ़कर आकर्षक एवं बिकने वाले मॉडल बनते रहते हैं और इन्हें शोरूम तक पहुंचाने के लिए ट्रकें कतारी में खड़ी रहती हैं। पास में ही एक ढाबे में कामगारों की भीड़ देखी जा सकती है। 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के बाद हालात बिल्कुल बदल गए हैं। परिस्थितियां विकट होती जा रही हैं और देश के कई इलाकों से आए लोगों की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। गुड़गांव में दोपहिया कंपनी हीरो के संयंत्र के सामने चाय स्टॉल लगाने वाले रूपेन महतो कहते हैं, 'सामान्य दिनों में मैं रोजाना हरेक दिन 450 कप चाय बेचता था। बंदी के बाद सब कुछ थम गया है।' वाहन उत्पादन के इस प्रमुख क्षेत्र में अग्रणी विनिर्माता कंपनियों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच संवाद का पुख्ता तंत्र मौजूद है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यहां मारुति, हीरो, होंडा जैसी वैश्विक वाहन कंपनियों और कल-पुर्जे मुहैया करने वाली डेंसो, बॉश और रीको जैसी दिग्गज कंपनियां भी हैं। हालांकि इन कंपनियों में विनिर्माण के ज्यादातर कार्य स्वचालित होते हैं, लेकिन उत्पादन इतना अधिक होता है कि कंपनियों को अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती हैं। ये श्रमिक वाहन चढ़ाने, उन्हें ढोने और कैंटीन संभालने में लगाए जाते हैं।

लॉकडाउन के बाद ज्यादातर मजदूर अपने गांव लौट गए हैं। हालत नाजुक होते देख ये कंपनियां पवन जैसे लोगों को रोके रखना चाहती हैं। मारुति सुजूकी ने अपनी कैंटीन खुली रखी है और यहां से कसान गांव में रोज 7,000 डिब्बा बंद खाने का वितरण हो रहा है। (शेष पृष्ठ 8)

संक्षेप में

जेएसपीएल को कोलकाता मेट्रो से मिला ऑर्डर

निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनी जिंदल स्टील ऐंड पावर लि. (जेएसपीएल) को कोलकाता मेट्रो रेल निगम (केएमआरसी) से 2,308 टन पटरी का ऑर्डर मिला है। कंपनी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जेएसपीएल केएमआरसी को हेड हार्डेंड पटरी की आपूर्ति करनी है। इस विशेष पटरी का इस्तेमाल द्रुत गति के ढुलाई गलियारे और सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं में होता है। जेएसपीएल के प्रबंध निदेशक वी आर शर्मा ने कहा, हमें केएमआरसी से 1080 एचएच ग्रेड की 2,308 टन पटरी की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। रेल मंत्रालय के तहत अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (एफडीएसओ) ने 60ई। ग्रेड और 1080 एचएच ग्रेड हेड हार्डेंड पटरी के विनिर्माण एवं आपूर्ति की मंजूरी दे दी है। *भाषा*

मांग घटने से गेल ने बंद किया पेट्रोरसायन संयंत्र

सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश स्थित अपने पाटा पेट्रोरसायन संयंत्र को बंद कर दिया है। इसकी प्रमुख वजह देशव्यापी लॉकडाउन (बंद) की वजह मांग का गिरना और माल की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गेल ने पहले अपने पाता संयंत्र की सालाना उत्पादन क्षमता में 4,00,000 टन में आधी कटौती की थी। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सार्वजनिक पाबंदी के बाद कंपनी ने अपने तैयार उत्पादों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों के दो तिहाई ट्रकों का उपयोग रोक दिया है। *भाषा*

बेहतर उत्पादन के लिए साथ आईं फार्मा कंपनियां

फार्मा कंपनियों में 60-70 प्रतिशत पर पहुंचा क्षमता उपभोग, सिक्किम में शत प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर रहे फार्मा प्लांट

सोहिनी दास
मुंबई, 12 अप्रैल

भारत का फार्मा उद्योग इस कठिन समय में आवश्यक दवाइयों के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सभी कोशिशें कर रहा है जिससे दवाइयों की कमी से न जूझना पड़े। एक अहम कदम उठाते हुए सभी प्रमुख कारोबारी अपनी अपनी समझ तथा ज्ञान को साझा कर रहे हैं जिससे जमीनी स्तर पर चीजें ठीक की जा सकें। छोटे तथा बड़े सभी विनिर्माताओं को मिलाकर देश भर में फार्मा उद्योग का क्षमता उपयोग इस समय 60-70 प्रतिशत पर है, जो किसी भी दूसरे उद्योग के मुकाबले काफी ज्यादा है।

भारत की 25 शीर्ष फार्मा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लॉबी समूह भारतीय फार्मास्युटिकल अलायंस (आईपीए) ने यह संभव किया है। समूह ने बताया कि कोरोना संकट के बाद भी सभी शीर्ष कंपनियां सामान्य रूप से परिचालन करने में सक्षम हैं। लगभग सभी प्रमुख दवा कंपनियों की सिक्किम में अपनी इकाइयां हैं। सिक्किम में दवाइयों का उत्पादन सामान्य है। उद्योग का दावा है कि यहां सभी संयंत्र शत-प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।

कैडिला हेल्थकेयर के अध्यक्ष पंकज पटेल ने कहा कि सिक्किम में घरेलू चिकित्सा उत्पादन करने वाली जायडस कैडिला जैसी कंपनियों के लिए घरेलू उत्पादन सामान तरीके से हो रहा है। इसी तरह एलेम्बिक फार्मा का सिक्किम स्थित संयंत्र पूरी क्षमता के साथ उत्पादन कर रहा है। आईपीए के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि शीर्ष 20 कंपनियों में से अधिकांश कंपनियों की सिक्किम में विनिर्माण इकाई है जहां बिना किसी बाधा के परिचालन हो रहा है।

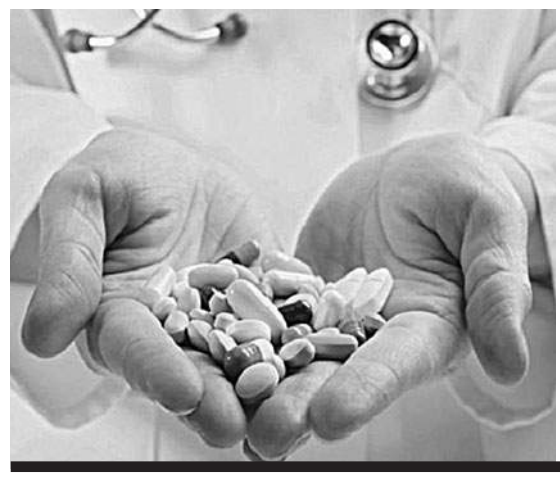

- छोटे तथा बड़े सभी विनिर्माताओं को मिलाकर देश भर में फार्मा उद्योग का क्षमता उपयोग इस समय 60-70 प्रतिशत पर
- शीर्ष 20 कंपनियों में से अधिकतर की विनिर्माण इकाई सिक्किम में है जहां बिना किसी बाधा के परिचालन हो रहा है

जैन ने कहा कि तीन प्रमुख उद्योग संघों, आईपीए, मध्यम आकार की फर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) और बहुराष्ट्रीय फर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्युटिकल्स प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया (ओपीपीआई) किसी भी निर्माता के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने तथा उसका समाधान खोजने के लिए रोज बैठकें कर रहे हैं।

जैन ने कहा, 'यह अभूतपूर्व है और संकट ने हमें एक साथ ला दिया है। इसके अलावा कंपनियां संसाधनों के स्तर पर भी एक-दूसरे की मदद भी कर रही हैं। उदाहरण के लिए, इंदौर, गोवा आदि विनिर्माण क्षेत्रों में कंपनियां ट्रक जैसे संसाधानों का एक साथ उपयोग कर रही हैं और संबंधित क्षेत्र में किसी भी नियामकीय बाधाओं के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं।'

वह बताते हैं, 'मान लीजिए, सिप्ला तथा ल्यूपिन अपने मामलों पर बात करने के लिए राज्य प्रशासन के पास जाती हैं, सामने आ रही चुनौतियां समझती हैं और अपनी जरूरतें बताती हैं। इसके बाद, कंपनियां बेहतर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों को साझा करने पर भी विचार करती हैं।'

फार्मा उद्योग ने संयंत्रों में काम करने के लिए आने वाले अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। आईपीए ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं और ज्यादातर कंपनियां इनका पालन कर रही हैं। कारखाने से लेकर कैंटीन तक सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। पटेल बताते हैं कि कर्मियों को लाने वाली बस में प्रत्येक दूसरी सीट खाली छोड़ी गई है तथा इन बसों को दिन में दो बार सैनिटाइज किया जाता है। संयंत्र में आने वाले प्रत्येक कर्मी की तापमान स्क्रीनिंग से जांच की जाती है।

दूसरे उद्योगों के सामने प्रवासी श्रमिक बड़ी समस्या हैं लेकिन फार्मा उद्योग के साथ ऐसा नहीं है। एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स के अध्यक्ष प्रणव अमीन बताते हैं कि फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र में एक निश्चित स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और आमतौर पर कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति उस शहर में ही बस जाता है। उन्होंने कहा, 'हमारे कर्मियों ने किसी तरह का पलायन नहीं किया। हमारी इकाइयों में कार करने वाले कुल प्रवासी श्रमिक थे जिनके लिए हमने अलग से छात्रावासों की व्यवस्था करा दी जिससे उन्हें असुरक्षित महसूस न हो।'

एलेम्बिक का फॉर्मूलेशन संयंत्र 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर काम कर रहा है जबकि इसकी सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) इकाई लगभग 60-70 प्रतिशत क्षमता पर चल रही है। कंपनी एजित्कोमाइसिन जैसी अधिक मांग वाली दवाइयों के विनिर्माण को प्राथमिकता दे रही है।

गुजरात की एक अन्य कंपनी जायडस हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन (एचसीक्यू) के निर्माण वाली अग्रणी कंपनी है और इसने अपनी क्षमता पहले ही कई गुना बढ़ा दी है। पटेल बताते हैं, 'इस महीने हम 10 टन एपीआई बना रहे हैं, जिससे 10 करोड़ टेबलेट बन सकती हैं। अगले महीने हम 30 टन एपीआई बनाएंगे, जिनसे 15 करोड़ टेबलेट बनाएंगे।' एचसीक्यू उत्पादन के अस्थायी उपाय के तौर पर कंपनी ने अहमदाबाद संयंत्र में भी इसका उत्पादन शुरू किया है।

पटेल ने यह भी बताया कि केंद्र ने करीब 10 करोड़ टेबलेट खरीदी हैं और राज्यों ने मिलकर छह से सात करोड़ टेबलेट खरीदी हैं। इससे देश में एक करोड़ से अधिक लोगों की देखभाल हो सकती है। वर्तमान में तेवा की गोवा इकाई से निर्यात हो रहा है, जहां पहले से ही इसका भंडार था।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग, वाणिज्य मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय के समन्वय के साथ दवाइयों का निर्यात किया जा रहा है। पटेल ने कहा, 'सरकार घरेलू उत्पादन और इनवेंटरी का नियमित रूप से स्टॉक कर रही है और निर्यात की अनुमति दे रही है। देश में दवाओं की कोई कमी नहीं होगी।'

उद्योग ने महसूस किया कि सरकारी एजेंसियां देश के भीतर इन आवश्यक दवाओं के निर्बाध उत्पादन एवं आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। जैन ने कहा कि शीर्ष नौकरशाह प्रमुख संघों के व्हाट्सएप समूहों में हैं और किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए चौबीस घंटे उपलब्ध हैं। एआईओसीडी-एडब्ल्यूएसीएस द्वारा जारी डेटा से पता चला कि वितरक स्तर पर दवाइयों का पर्याप्त भंडारण है।

टाटा स्टील जुटाएगी रकम

अदिति दिवेकर
मुंबई, 12 अप्रैल

इस्पात बनाने वाली देश की सबसे पुरानी कंपनी टाटा स्टील 10,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के झटके से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले महीने प्रणाली में अतिरिक्त नकदी डालने के लिए विशेष व्यवस्था की घोषणा की थी। इसके बाद कई कंपनियां नकदी जुटाने की पहल कर रही हैं।

इस मामले से अवगत एक सूत्र ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'बाजार से जुटाई जाने वाली नकदी को अधिकतर कंपनियां अतिरिक्त नकदी भंडार के रूप में बचाकर रखेंगी और उसका इस्तेमाल लॉकडाउन के बाद लघु अवधि के ऋण अदायगी में किया जा सकता है।' टाटा स्टील एकमात्र ऐसी कंपनी नहीं है जो केंद्रीय बैंक के इस निर्णय का फायदा उठाते हुए रकम जुटाने की कोशिश कर रही है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2 अप्रैल को कहा था कि उसके बोर्ड ने एनसीडी के जरिये 25,000 करोड़ रुपये तक रकम जुटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने कहा कि भारतीय एयरटेल भी लगभग 10,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है।

- टाटा स्टील 10,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है
- रकम का इस्तेमाल लॉकडाउन के बाद लघु अवधि के ऋण अदायगी में किया जा सकता है

कोविड-19 के प्रकोप के कारण पैदा हुए आर्थिक व्यवधान से निपटने के लिए एक उपाय के तौर पर आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपये के लिए कम दर पर ऋण वितरण के लिए विशेष व्यवस्था की है। आरबीआई ने पिछले महीने एक बयान में इसकी घोषणा की थी। नियामक ने 27 मार्च को प्रणाली में नकदी प्रवाह बढ़ाने का निर्णय लिया था ताकि कोविड-19 के कारण पैदा हुए व्यवधान के बीच वित्तीय बाजार और संस्थान सुचारु तौर पर परिचालन कर सकें।

घरेलू और वैश्विक बाजार में इस्पात के लिए कमजोर मांग परिदृश्य के कारण भी टाटा स्टील अतिरिक्त नकदी जुटाने की पहल कर रही है ताकि आगामी तिमाहियों में उसके मार्जिन पर कोई झटका न लगे। फिलहाल दुनिया भर में फैली कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए 30 अप्रैल तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी रहने के आसार हैं। ऐसे में इस्पात की मांग आगे और प्रभावित होगी।

एडलवाइस रिसर्च ने अपने एक नोट में कहा, 'हमें घरेलू इस्पात कीमतों के लिए जोखिम बढ़ता दिख रहा है और निकट भविष्य में मांग में तेजी आने के आसार कम हैं।' दिसंबर 2019 के अंत में टाटा स्टील का सकल ऋण बोझ 1,09,867 करोड़ रुपये था।

'छोटे और बड़े दोनों पैक के लिए बढ़ेगी मांग'

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं (एफएमसीजी) का बाजार काफी प्रभावित हुआ है और ऐसे में कंपनियां अपनी कारोबारी रणनीति नए सिरे से तैयार करने में जुट गई हैं। गोदरेज कंज्यूमर के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी **विवेक गंभीर** ने **विवेट सुजन पिंटो** से बातचीत में लोगों की उपभोग संबंधी आदतों में बदलाव और कंपनी की रणनीति के बारे में विस्तृत चर्चा की। पेश हैं मुख्य अंश:

गोदरेज कंज्यूमर (जीसीपीएल) ने हाल में कहा था कि वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के कारण मार्च तिमाही के नतीजे प्रभावित होंगे। आप कितनी तेजी से स्थिति में सुधार देख रहे हैं?

हम उभरती स्थिति से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान वितरण एवं उत्पादन दोनों मोर्चे पर व्यवधान उत्पन्न हुए हैं और हमारा परिचालन बाधित हुआ है। हालांकि लॉकडाउन की अभूतपूर्व प्रकृति को देखते हुए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। सरकार इन चुनौतियों से अवगत है और वह आपूर्ति श्रृंखला को जल्द से जल्द पटरी पर लाने के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम कर रही है।

पिछले कुछ दिनों से हम आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह तेजी कम क्षमता पर की जा रही है। हमारी फैक्टरियों में उत्पादन का स्तर 25 से 30 फीसदी है। हमारे 60 से 70 फीसदी डिपो खुले हैं और 25 से 30 फीसदी वितरकों को परिचालन की अनुमति मिली है। सबसे बड़ी चुनौती श्रमिकों की किल्लत की है। कुछ चुनौतियां डर और सामाजिक दबाव के कारण पैदा हुई जबकि कुछ प्रवासी मजदूरों के वापस जाने से। हालांकि धीरे-धीरे मंजूरियां मिल रही हैं लेकिन पर्याप्त कार्यबल अब भी उपलब्ध नहीं है।

अब लॉकडाउन के बढ़ने की संभावना है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि उद्योग जगत की परेशानी कहीं अधिक बढ़ जाएगी?

वायरस के फैलने की रोकथाम, आपूर्ति श्रृंखला में सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में एक प्रकार से संतुलन होना चाहिए। हमें लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से संयंत्रों को खोलना चाहिए ताकि सामाजिक दूरी को अनिवार्य तौर पर पालन किया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरुआत करेंगे और उसके बाद 2 से 4 सप्ताह में 75 फीसदी और यदि यह महामारी नियंत्रित हो गई तो 8 सप्ताह में 100 फीसदी क्षमता पर परिचालन करेंगे।

एफएमसीजी उद्योग आपूर्ति श्रृंखला में हरेक मोर्चे पर मानदंड स्थापित करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें स्वच्छता प्रोटोकॉल, सामाजिक दूरी संबंधी मानदंड, सैनिटाइजेशन और अच्छी तरह से साफ-सफाई के अलावा श्रमिकों के साथ जागरूकता सत्र आदि शामिल हैं।

बाजार में सुधार कब तक दिखने की उम्मीद है?

यह दो हिस्सों की कहानी है जो इस बात पर निर्भर करती है कि संकट कितने लंबे समय तक रहता है। यहां तक कि यदि लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाता है तो भी इसका मतलब यह नहीं होगा कि संकट खत्म हो गया। वैश्विक महामारी कहीं अधिक लंबे समय तक चल सकती है। जहां तक योजना बनाने का सवाल है तो जीसीपीएल में हमारा मानना है कि इस वायरस के प्रभाव को वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में कहीं अधिक महसूस किया जाएगा। साथ ही दूसरी तिमाही में भी उसका कुछ असर दिखेगा। लेकिन यदि संकट कम होता है तो आप दूसरी छमाही को पहले के मुकाबले काफी अलग देखेंगे।

इस संकट के बाद खपत में क्या बदलाव आएगा?

उद्योग में ढांचागत बदलाव दिखेगा। उपभोक्ताओं की कुछ आदलतों में काफी बदलाव आ सकता है। विश्वास काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता पर काफी ध्यान देंगे। आमतौर पर युवा लोग ऑनलाइन अधिक खरीदारी करेंगे। अब पुरानी पीढ़ी भी ऑनलाइन खरीदारी को तेजी से अपनाएगी। किराने की दुकानों में तेजी आएगी क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आसपास के लोगों का उन पर भरोसा बढ़ा है। साथ ही हमें छोटे और बड़े दोनों पैक की बढ़ती मांग के बीच बाजार में ध्रुवीकरण दिखेगा।

जीसीपीएल इस बदलाव के लिए किस प्रकार तैयारी कर रही है?

हमारे कारोबार को नए सिरे से तैयार करने, नवाचार के लिए पोर्टफोलियो पर नए सिरे से गौर करने और नए दांव लगाने के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण असर है। हमारे लिए यह लगातार जारी रहने वाली यात्रा है चाहे पुरुष सौन्दर्य उत्पाद हो अथवा एयर फ्रेशनर या फिर लिक्विड डिटरजेंट। बाजार के लिए हमारी रणनीति में काफी बदाव दिखेगा। हमने ई-कॉमर्स पर केंद्रित एक अलग कारोबारी इकाई भी बनाई है।

अगले सप्ताह नतीजे की घोषणा करेगी विप्रो

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 12 अप्रैल

प्रमुख आईटी सेवा कंपनी विप्रो अगले सप्ताह आईटी उद्योग के लिए वित्तीय नतीजे की शुरुआत करेगी। आमतौर पर टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज (टीसीएस) और इन्फोसिस वित्तीय नतीजे के सीजन की शुरुआत करती रही हैं। विप्रो 15 अप्रैल को चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजे के साथ-साथ वार्षिक वित्तीय परिणाम भी जारी करेगी। जबकि बाजार की अग्रणी कंपनी टीसीएस अगले दिन यानी 16 अप्रैल को अपने वित्तीय नजीतों की मंजूरी के लिए बोर्ड बैठक आयोजित करेगी। इन्फोसिस ने फिलहाल निवेशकों को यह नहीं बताया है कि वह किस दिन चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी करेगी।

सूत्रों ने कहा कि विप्रो आबिदअली नीमचवाला के इस्तीफे के बाद अपने नए सीईओ के नाम की घोषणा भी कर सकती है। फरवरी के पहले सप्ताह में नीमचवाला ने पारिवारिक कारणों का उल्लेख करते हुए इस्तीफा दे दिया था। नीमचवाला की जगह विप्रो के नए सीईओ के प्रमुख दावेदारों में एक्सेंचर टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ग्रुप सीईओ भास्कर घोष, एक्सचेंर के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी उमर अब्बोश और इन्फोसिस के अध्यक्ष एवं उप मुख्य परिचालन अधिकारी एस रवि कुमार शामिल हैं। मार्च में कोविड-19 के कारण कारोबार प्रभावित होने के बावजूद अधिकतर घरेलू आईटी सेवा कंपनियां राजस्व और मुनाफे में वृद्धि दर्ज कर सकती हैं। हालांकि वित्त वर्ष 2021 के लिए कारोबारी परिदृश्य में इस वैश्विक महामारी के कारण मांग में नरमी दिख रही है।

बंगाल केमिकल्स बना रही एचसीक्यू

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 12 अप्रैल

देश की सबसे पुरानी औषधि कंपनी बंगाल केमिकल्स ऐंड फार्मास्युटिकल्स (बीसीपीएल) कोविड-19 के उपचार में सबसे अधिक मांग वाली दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) की बढ़ती मांग के कारण सुर्खियों में है। वर्ष 1892 में स्थापित बीसीपीएल कभी एचसीक्यू का उत्पादन करती थी लेकिन नकदी किल्लत एवं श्रमिक समस्याओं के कारण दशकों पहले उसने मलेरियारोधी इस दवा का उत्पादन बंद कर दिया था।

कंपनी ने पश्चिम बंगाल के औषधि नियंत्रक निदेशालय से एक बार फिर इस दवा का उत्पादन शुरू करने के लिए लाइसेंस हासिल किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में इस दवा को काफी महत्त्वपूर्ण बताया है। हालांकि बीसीपीएल को अब कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यह एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) है जो एचसीक्यू एवं अन्य मलेरियारोधी दवाओं का उत्पादन कर सकता है।

कंपनी 20 मार्च से ही कच्चे माल के लिए कोशिश कर रही है लेकिन वह अब तक खरीद नहीं पाई है।

- इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को प्रमुख कच्चे माल की आपूर्ति में हो रही बाधा
- कंपनी 20 मार्च से ही कच्चे माल के लिए कोशिश कर रही है लेकिन वह अब तक खरीद नहीं पाई है
- वर्तमान क्षमता पर बीसीपीएल रोजाना 10 लाख एचसीक्यू और क्लोरोक्वीन फॉस्फेट टैबलेट का उत्पादन कर सकती है

बीसीपीएल के प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और निदेशक (वित्त) पीएम चंद्रैया ने कहा, 'कच्चे माल की खरीद में फिलहाल कोई सफलता नहीं मिली है और यह एक बड़ी बाधा है जो एचसीक्यू के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा हम एक छोटी कंपनी हैं और इस मोर्चे पर हमारे संसाधन भी सीमित हैं।' उन्होंने कहा, 'कल्पना कीजिए कि किसी खास टैबलेट की मांग 10 लाख से अचानक बढ़कर 1 करोड़ हो जाए। ऐसे में यदि आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध न हो तो क्या कोई कंपनी मांग को पूरा कर पाएगी?'

बीसीपीएल के पास क्लोरोक्वीन फॉस्फेट के उत्पादन का भी लाइसेंस है। यह एक अन्य मलेरियारोधी दवा है जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के उपचार में किया जा रहा है। इन दोनों दवाओं का बुनियादी फॉर्मूलेशन सिनकोना पौधे की छाल और कुछ अन्य कृत्रिम रसायनों के अर्क पर आधारित है। सबसे अहम बात यह है कि बीसीपीएल के पास क्लोरोक्वीन फॉस्फेट के उत्पादन के लिए मौजूद सभी कच्चे माल खत्म हो चुके हैं और अब वह कच्चे माल की आपूर्ति का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा, 'हमारे पास 15 से 16 राज्य सरकारों से 20 लाख टैबलेट के ऑर्डर थे। हम करीब 8 लाख टैबलेट बनाने में सफल रहे हैं और अधिक उत्पादन के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होगी।' वर्तमान उत्पादन क्षमता पर बीसीपीएल रोजाना 10 लाख एचसीक्यू और क्लोरोक्वीन फॉस्फेट टैबलेट का उत्पादन कर सकती है।

चंद्रैया ने कहा कि बीसीपीएल के परिचालन एवं श्रमबल संबंधी समस्याओं को देखते हुए यदि स्थानीय प्रशासन कंपनी को कच्चा माल हासिल करने में मदद करती है तो काफी राहत मिलेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने एचसीक्यू बनाने के लिए औषधि कंपनियों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करने के लिए कदम बढ़ाया है। इसी क्रम में उसने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है ताकि कुरसियोंग जिले के मोंगपु में सिनकोना के बागानों को फिर से शुरू किया जा सके। करीब 9,600 एकड़ में विस्तृत इस बागान में पौधारोपण करीब 15 वर्ष पहले बंद कर दिया गया था।

बीसीपीएल भारत की सबसे पुरानी औषधि कंपनी है जो कई जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करती है। हालांकि 1965 में कंपनी को जबरदस्त वित्तीय समस्याओं से जूझना पड़ा था और उसके बाद 1977 में केंद्र सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया। चंद्रैया ने कहा कि कंपनी दशकों तक कार्यशील पूंजी की कमी, श्रमबल एवं वित्तीय समस्याओं एवं औद्योगिक समस्याओं से जूझती रही। इन सब कारणों से उसे एचसीक्यू जैसी अन्य प्रमुख जेनेरिक दवाओं का उत्पादन बंद करना पड़ा।

सुपरस्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर ?

सुरक्षित दांव पर निवेशकों का जोर और आय के मोर्चे पर बेहतर स्पष्टता के कारण मूल्यांकन हुआ है महंगा, लिहाजा गिरावट की संभावना में हो रहा है इजाफा

विशाल छाबड़िया और श्रीपाद एस ऑटे
मुंबई, 12 अप्रैल

ऐसी दुनिया में जहां बढ़त हासिल करना दुर्लभ हो गया हो, अग्रणी विश्लेषक वैश्विक मंदी की भविष्यवाणी कर रहे हों और भारत की जीडीपी की रफ्तार में कटौती कर उसे कई साल के निचले स्तर पर ले जा रहे हों तो स्थिर आय की पेशकश करने वाली कंपनी की ओर निवेशक खिंचे चले आएंगे और उसका मूल्यांकन प्रीमियम से लैस होगा। ऐसी चुनिंदा कंपनियों में से एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है और पिछले एक महीने में कंपनी का शेयर 12 फीसदी चढ़ा है जबकि निफ्टी में 13 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। एचयूएल अभी दिसंबर 2019 में समाप्त पिछले 12 महीने की आय के करीब 75 गुने पर कारोबार कर रही है, जो पांच साल के औसत के मुकाबले 55 फीसदी प्रीमियम दर्शाता है और निफ्टी-50 के पीई मूल्यांकन से पांच गुना ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन स्तरों पर इतनी भारी भरकम प्रीमियम चुकाए जाने में खतरा है। अपनी मूल कंपनी यूनिलीवर से तुलना करने पर भी एचयूएल काफी ऊंचा मूल्यांकन दर्शाती है।

प्रभुदास लीलाधर के सीईओ (पीएमएस) अजय बोडके ने कहा, एचयूएल का मूल्यांकन निवेशकों का अतार्किक कसरत दर्शाता है। यह एचयूएल की फ्रैंचाइजी के उचित मूल्यांकन को लेकर एक तरह का भ्रम बताता है, जो यूनिलीवर के मुनाफे में 13.8 फीसदी का योगदान करता है, लेकिन उसके बाजार मूल्यांकन में हिस्सेदारी 54 फीसदी है।

नेस्ले इंडिया का शुद्ध लाभ नेस्ले एसए का महज 2.2 फीसदी और मूल कंपनी के बाजार मूल्यांकन का 6.8 फीसदी। शुद्ध रूप से भारतीय संदर्भ में नेस्ले इंडिया का शेयर महंगा है, लेकिन वैश्विक संदर्भ में नेस्ले इंडिया के मुकाबले एचयूएल अपनी मूल कंपनी के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम पर कारोबार कर रही है। एचयूएल का बाजार मूल्यांकन 5.14 लाख करोड़ रुपये है, जो भारत की 10 सूचीबद्ध ऑटोमोबाइल कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण 4.20 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। निश्चित तौर पर टाटा मोटर्स, एमऐंडएम और टीवीएस मोटर जैसी कंपनियों के ऊपर भारी-भरकम कर्ज (संयुक्त रूप से शुद्ध कर्ज 1.34 लाख करोड़ रुपये) है, लेकिन बाकी अन्य कंपनियां कर्ज मुक्त हैं या फिर उनके पास सरप्लस नकदी है।

ऐसे करीब 15 उदाहरण हैं जहां किसी एक क्षेत्र की सभी सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मूल्यांकन एचयूएल से कम है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र की तरह उन्होंने ज्यादा मुनाफा अर्जित किया। यह हालांकि सख्ती के साथ तुलनायोग्य नहीं हो सकता क्योंकि कारोबारी मॉडल, कर्ज का स्तर, पूंजी की दक्षता और बढ़त के अनुमान अलग-अलग होते हैं। लेकिन ऐसी तुलना एचयूएल के बाजार मूल्यांकन का परिप्रेक्ष्य बताता है।

मूल कंपनी से मंहगा

आंकड़े करोड़ रुपये में	यूनिलीवर पीएलसी	हिंदुस्तान यूनिलीवर
राजस्व	4,09,976	40,773
शुद्ध लाभ	52,711	6,804
ईपीएस (रुपये)	200.6	31.3
पीई (गुणक)	20.3	75.5
बाजार पूंजीकरण	10,72,185	5,13,696

ईपीएस : प्रति शेयर आय। पीई : प्राइस टु अर्निंग अनुपात दिसंबर 2019 तक के पिछले 12 महीने के। बाजार पूंजीकरण : 9 अप्रैल, 2020
स्रोत : ब्लूमबर्ग, कंपनी

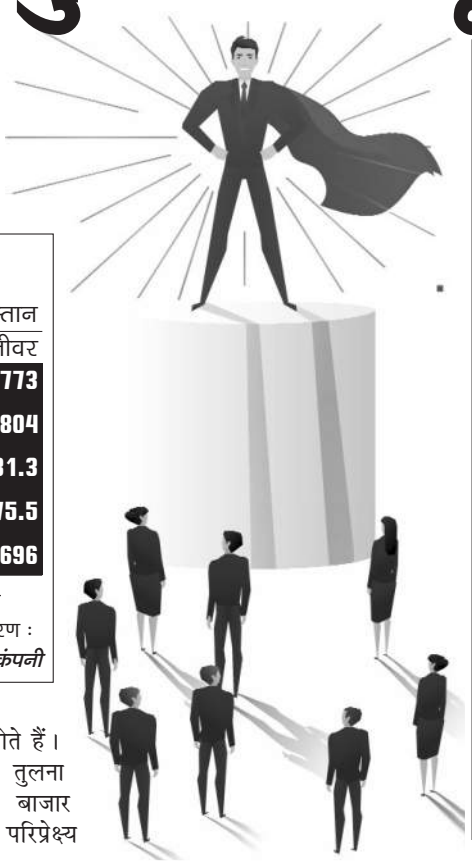

अन्य विशेषज्ञों ने भी बोडके की राय का समर्थन किया। सेंट्रम ब्रोकिंग के विश्लेषक शिरीष परदेशी ने कहा, हालांकि एचयूएल की आय पर स्पष्टता और बढ़त की क्षमता बेहतर है और सुरक्षित ठिकाने की ओर निवेशकों के जाने के कारण इस तरह का सुपर मूल्यांकन देखने को मिला है। फिलिप कैपिटल के उपाध्यक्ष विशाल गुटका ने कहा, कोविड-19 की महामारी और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद के बीच अन्य क्षेत्रों के कमजोर परिदृश्य से एचयूएल में तेजी देखने को मिली है।

मजबूत फंडामेंटल के अलावा अच्छा कारोबारी मॉडल और कर्ज मुक्त बैलेंस शीट, एचयूएल का विस्तृत वितरण नेटवर्क, मजबूत ब्रांड इक्विटी और विशाल प्रॉडक्ट मिक्स, आवश्यक वस्तुओं में खासी हिस्सेदारी काफी सहजता प्रदान करता है। यूबीएस सिक्योरिटीज के मुताबिक, वितरण के विश्लेषण के आधार पर एचयूएल वैसी चुनिंदा कंज्यूमर कंपनियों में शामिल है जो अपनी रणनीति के कारण अंतिम छोर पर तब भी पहुंच में सुधार लाने के लिहाज से बेहतर स्थिति में है जब अन्य कंपनियां वितरण में अवरोध का सामना कर रही हैं।

एचयूएल को मौजूदा हालात में कमजोर कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी मिल सकती है। बोडके ने हालांकि कहा कि एचयूएल की अंतर्निहित आय ज्यादा है तो यह भी समझने योग्य है। इसका श्रेय उसकी मजबूत बैलेंस शीट और नकदी सृजन की बेहतर क्षमता को दिया जाना चाहिए। उसकी आय में बढ़त की स्थायी रफ्तार 14-15 फीसदी अनुमानित है (ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर के अधिग्रहण समेत)।

गैर-आवश्यक पोर्टफोलियो (यूबीएस के मुताबिक 9 फीसदी राजस्व) मौजूदा परिस्थितियों में किस करबट बैठता है, उस पर भी नजर रखनी होगी। इसके अलावा ग्रामीण व शहरी मांग पर भी संशय है क्योंकि नौकरियों के नुकसान और वेतन में कटौती के कारण आय में संभावित कमी हो सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में भी कोविड-19 के कारण भारत पर गंभीर आर्थिक जोखिम की बात कही गई है। ऐसे में एचयूएल की आय पर भी जोखिम है। इसके अतिरिक्त विगत में भी ऐसे मामले देखे गए हैं जब बाजार ने उसे दंडित किया है। फरवरी 2000 और साल 2001 के आखिर के बीच जब तकनीक, मीडिया और दूरसंचार का बुलबुला फूटा था तब विप्रो का शेयर 6,700 रुपये से 1,500 रुपये पर आ गया था, इन्फोसिस का 10,960 रुपये से 3,300 रुपये पर और जी का शेयर 1,350 रुपये से 50 रुपये के स्तर पर। साल 2008 में रियल एस्टेट का शेयर भी इसी तरह धराशायी हुआ था। वोडके ने चेतावनी देते हुए कहा है, निवेशकों को मूल्यांकन वास्तविक स्तरों पर लाने की दरकार है। एचयूएल के शेयर भाव को लेकर बड़ा जोखिम है। हालांकि ब्लूमबर्ग की रायशुमारी में शामिल 42 विश्लेषकों में से 30 ने एचयूएल की खरीद की सलाह दी है, लेकिन उनका एक साल का औसत लक्षित कीमत 2,281 रुपये 4 फीसदी की गिरावट का संकेत देता है। गुटका ने कहा, ऐसे महंगे भाव पर जीएसके पीएलसी (जिसे जीएसके की बिक्री के चलते एचयूएल का शेयर मिलना है) को एफएमसीजी दिग्गज की 5.7 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का लुभावना मौका दिख सकता है। यह एचयूएल के शेयरों पर दबाव डाल सकता है। परदेसी ने कहा, जब अन्य क्षेत्रों की बढ़त का परिदृश्य सामान्य हो जाएगा तब मूल्यांकन में गिरावट हो सकती है। तथापि एचयूएल भी कोविड-19 महामारी से प्रभावित होगी।

कुछ क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा मूल्यवान

कंपनी/क्षेत्र	शुद्ध बिक्री	शुद्ध लाभ	बाजार मूल्यांकन
आईटी-सॉफ्टवेयर	5,25,178	81,432	13,63,510
रिफाइनरीज	17,41,534	68,516	9,63,421
फार्मास्युटिकल्स	2,58,417	26,121	7,63,309
एफएमसीजी (एचयूएल को छोड़कर)	1,14,949	11,108	6,14,933
एचयूएल	**40,773**	**6,804**	**5,13,696**
ऑटोमोबाइल	5,95,585	20,995	4,19,503
बिजली उत्पादन व वितरण	2,77,021	27,836	3,11,180
सीमेंट	1,59,536	11,769	2,59,064
तंबाकू उत्पाद	56,413	15,694	2,37,510
केमिकल	1,30,994	13,050	2,18,092
खनन व खनिज उत्पाद	2,15,574	31,524	1,51,087
गैस वितरण	1,31,922	12,969	1,35,462
तेल व प्राकृतिक गैस	4,46,785	18,334	1,08,168

बाजार मूल्यांकन 9 अप्रैल, 2020 को। शुद्ध बिक्री और शुद्ध लाभ दिसंबर 2019 में समाप्त पिछले 12 महीने के। आंकड़े : करोड़ रुपये में।
स्रोत : कैपिटालाइन। संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

बाजार हलचल

खरीदारी करने लगे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक

बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की वापसी से कई खुश हैं। पिछले तीन कारोबारी सत्र में एफपीआई ने 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर खरीदे और इस तरह से बाजार में 13 फीसदी की तेजी आई। दूसरी ओर देसी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली कर कुछ रकम निकालते नजर आए। मार्च में एफपीआई ने देसी इक्विटी से रिकॉर्ड 62,000 करोड़ रुपये निकाले, जिसके कारण बेंचमार्क सूचकांकों में 26 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। एक विश्लेषक ने कहा, स्पष्ट तौर पर आक्रामक राहत पैकेज और प्रमुख इलाकों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी थम जाने से जोखिम उठाने वाला माहौल फिर लौट आया है। सामान्य तौर पर एफपीआई अपनी दिशा तेजी से नहीं बदलते, जिसका मतलब यह हुआ कि बाजारों में तेजी दर्ज हो सकती है। उन्होंने कहा कि निफ्टी 9,300 की ओर बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते निफ्टी 9,112 अंक पर टिका। **समी मोडक**

इंडसइंड बैंक में निवेश सीमा के करीब एफपीआई

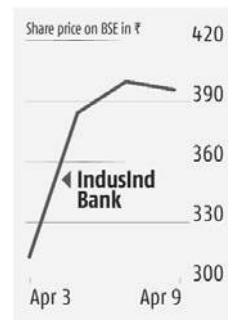

निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक में पिछले हफ्ते 26 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। डिपॉजिटरी फर्म एनएसडीएल की तरफ से इस शेयर को 'एफपीआई रेड फ्लैग' की सूची में जोड़ दिया, जिसके बाद इस शेयर में तेजी देखने को मिली। रेड फ्लैग तब जारी किया जाता है जब किसी शेयर में विदेशी निवेश की गुंजाइश कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सीमा से करीब 3 फीसदी कम रह जाती है। एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक, इंडसइंड बैंक के सिर्फ 1.2 करोड़ शेयर एफपीआई खरीद के लिए उपलब्ध हैं और विदेशी निवेशकों के पास 72.3 फीसदी शेयरधारिता है जबकि सीमा 74 फीसदी की है। एक विश्लेषक ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ बड़े एफपीआई ने शेयर कीमतों में गिरावट का फायदा उठाते हुए बैंक के काफी शेयर खरीदे हैं। हालिया सुधार से पहले इंडसइंड बैंक का शेयर कोविड-19 के दौरान बिकवाली के बीच साल 2020 के उच्चस्तर से 80 फीसदी से ज्यादा टूट चुका था। समी मोडक

मनी मैनेजरों के लिए बैक-अप की चिंता

एक परिसंपत्ति प्रबंधक हजारों किलोमीटर दूर देश के दूसरे इलाके में अपना कारोबार स्थापित किया, जो उसके कारोबार के सामान्य स्थल से वाकई काफी दूर था। विचार था इस केंद्र को आपदा के समय बैक-अप के तौर पर इस्तेमाल करने का। यानी अगर हम नाकाम होते हैं तो अन्य लोग कारोबार का परिचालन जारी रख सकते हैं। लॉकडाउन के कारण दोनों जगह समान रूप से प्रभावित हो गया। आखिरी बार सुना गया था कि इस बैक-अप ऑफिस ने जरूरी कामकाज को चालू रखा है, लेकिन वह भी सिर्फ 50 फीसदी क्षमता पर संचालित हो पा रहा है।
सचिन मामबटा

इंडेक्स फंडों में चार गुना बढ़ा निवेश

जश कृपलानी
मुंबई, 12 अप्रैल

निफ्टी और सेंसेक्स जैसे सूचकांकों के प्रदर्शन पर नजर रखने वाले इंडेक्स फंडों में मार्च के दौरान निवेश में चार गुने की उछाल दर्ज हुई। पिछले महीने ऐसे फंडों में 2,076 करोड़ रुपये का निवेश आया, जो इससे पिछले माह में 511 करोड़ रुपये रहा था। प्राइमइन्वेस्टर डॉट इन की सह-संस्थापक विद्या बाला ने कहा, टूटते बाजार में जहां सही इक्विटी फंड को चुनना मुश्किल होता है, वहीं इंडेक्स फंड लंबी अवधि के निवेश का नजरिया रखने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त होते हैं और उनके लिए भी जो बाजार की तरह ही रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। साथ ही इंडेक्स फंड के साथ एवरेज करना आसान होता है क्योंकि निवेशक मुख्य सूचकांकों मसलन निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट पर आसानी से नजर रख सकते हैं। मार्च में निफ्टी में 23.24 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई क्योंकि कोरोनावायस के प्रसार के बीच बिकवाली का दबाव गहरा गया। उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि निवेशकों को बाजार के मौजूदा माहौल में निष्क्रियता (पैसिवली) से प्रबंधित फंडों को लेकर सतर्क रहना चाहिए।

श्रीकवि वेल्थ के प्रबंध निदेशक श्रीकांत मटरूभाई ने कहा, निष्क्रियता से प्रबंधित फंडों ने तब जोर पकड़ा था जब बाजार स्थिर थे क्योंकि सक्रियता से प्रबंधित फंड संबंधित बेंचमार्कों को मात देने में अक्षम थे, जिसकी वजह इंडेक्स कुछ ही दिग्गज बाजार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उभरते बाजारों में सक्रिय रणनीति मंदी के बाजार में पोर्टफोलियो पर मार्क टु मार्केट नुकसान को लेकर सहारा देते हैं।

बिजनेस स्टैंडर्ड के हालिया अध्ययन से पता चलता है कि सक्रियता से प्रबंधित फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले तीन महीने में कम टूटे हैं। लार्जकैप व मिडकैप की योजनाओं की श्रेणी में 90 फीसदी तीन महीने में अपने बेंचमार्क के मुकाबले कम टूटे हैं।

ऑनलाइन म्युचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कुबेर के मुख्य कार्याधिकारी गौरव रस्तौगी ने कहा, कुछ चीजें इंडेक्स फंडों के हक में काम कर रही है। पहला, निवेशकों को अहसास हो रहा है कि इंडेक्स फंडों के लागत का मामला और कम खर्च अनुपात अलग से दिखता है। दूसरा, ऐक्टिव फंडों ने 2019 के तेजी के बाजार में इंडेक्स फंडों से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, जिसने ऐक्टिव फंडों को लेकर निवेशकों की अवधारणा पर चोट पहुंचाई।

म्युचुअल फंड के वितरकों ने निवेशकों को ईटीएफ के मुकाबले इंडेक्स चुनने की सलाह दी क्योंकि ईटीएफ में तरलता कम है और बाजार में तेज उतारचढ़ाव के दौरान उसे ट्रैक करने में काफी गलतियां हो सकती हैं।

एक फंड हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इंडेक्स से जुड़ाव रखने वाला ईटीएफ तकनीकी तौर पर निवेशकों को इंट्रा-डे के आधार पर एक्सचेंज में प्रवेश या निकासी की अनुमति दे सकता है, लेकिन उच्च उतारचढ़ाव के दौरान वे ट्रैकिंग में काफी गलतियां देख सकते हैं, जैसा कि हाल के महीनों में पाया गया। बाजार की हालिया बिकवाली में ईटीएफ कारोबारी सत्र के चरणों के दौरान सकारात्मक रहे हैं, जब बाजार 7-8 फीसदी नीचे थे। इसी तरह वे उस बदलाव को ट्रैक करने में अक्षम रहे जब बाजारों में तेज बढ़ोतरी आई थी।

बीएस बातचीत

'विविधता प्राप्त वैश्विक, अमेरिका केंद्रित फंडों से निकासी ज्यादा'

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) मार्च में भारतीय शेयरों से करीब 62,000 करोड़ रुपये निकाल चुके हैं। नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध 2002 तक के आंकड़ों के अनुसार किसी बड़ी निकासी थी। ईपीएफआर ग्लोबल में निदेशक **कैमरन ब्रांट** ने **पुनीत वाधवा** से बातचीत में कहा कि कोविड-19 संकट से पहले ही भारत को लेकर विदेशी निवेशकों का उत्साह ठंडा पड़ता रहा है। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

विकसित और तेजी से उभरते बाजारों से कितनी रकम की निकासी हुई है?
फरवरी के अंत में कोरोनावायरस के डर से बिकवाली शुरू होने से पहले बॉन्ड फंडों, खासकर अमेरिकी बॉन्ड फंडों में रकम झोंकी जा रही थी। इक्विटी फंडों में निवेश कमतर रहा था, लेकिन वैश्विक स्तर पर धाक रखने वाले फंडों में नए निवेश जरूर हो रहा था। तेजी से उभरते बाजार (ईएम) फंड समूहों में चीन और ब्राजील के इक्विटी फंडों में औसत से अधिक निवेश हुआ था। मार्च में बड़े पैमाने पर हलचल दिखी। मेरी समझ से कम नुकसान वाली परिसंपत्तियों की बिकवाली इसकी मुख्य वजह थी।

अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में बिकवाली अब अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच चुकी है या अभी और बुरा दौर आने वाला है?
मुझे नहीं ऐसा नहीं लगता। निवेश के महौल पर कोविड-19 का असर पड़ने से पहले ही भारत को लेकर निवेशकों का उत्साह कम हो गया था। पूंजीगत व्यय, महंगाई और भारत के बैंकिंग क्षेत्र की सेहत को लेकर निवेशक सोचने पर विवश हो गए थे।

क्या अगले कुछ महीनों में भारत में विदेशी निवेश में कुछ न कुछ तेजी आती रहेगी?
तेजी से उभरते बाजारों पर केंद्रित फंड समूह निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, भारत में कोविड-19 संकट से पहले ही मुश्किलें रही हैं। इन वजहों से निवेशकों की नजरों में भारत के प्रति आकर्षण घटता रहा है।

किन बाजारों से निवेशकों ने सबसे अधिक रकम निकाली है? रकम कहां लगाई गई है?
नकदी के लिहाज से बात करें तो विविधता वाले वैश्विक और अमेरिका एवं यूरोप पर केंद्रित फंडों से सबसे अधिक निकासी हुई है। जो रकम निकासी के बाद भी बाजार में दोबारा लगाई गई है, वह कई देशों के फंड समूहों में गई है। इनमें यूनाइटेड किंगडम, चीन, स्विटजरलैंड, जापान, ब्राजील और ताइवान इक्विटी फंड और जर्मनी बॉन्ड फंड शामिल हैं।

बाजार ने कोविड-19 को लेकर किस तरह प्रतिक्रिया दिखाई है? क्या बुरा दौर खत्म हो चुका है?
कई तरह की रणनीतियां अपनाई गई हैं और इन्हें विभिन्न स्तरों तक सफलता भी मिली है। इसके साथ ही विश्वसनीय जानकारियां भी सामने आई हैं। हालांकि अब भी बाजार में काफी अनिश्चितताएं हैं। कई प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं और यह खासकर पूछा जा रहा है कि क्या वायरस आगे भी पूरी दुनिया में कोलाहल मचाता रहेगा। इन वजहों से दूसरी बड़ी बिकवाली को नकारना जल्दबाजी होगी।

वैश्विक बाजारों और अर्थव्यवस्था को दोबारा सामान्य स्तर पर लौटने में कितना समय लग सकता है? कोविड-19 संकट से निवेशकों के उत्साह को कितना नुकसान पहुंचा है?
मुझे लगता है कि शेयर बाजार के मुकाबले बॉन्ड बाजार अधिक तेजी से वापसी करेंगे। दुनिया के केंद्रीय बैंकों और सरकारों से मदद के कई उपायों से बॉन्ड निर्गम और इन पर प्राप्तियों का समीकरण बिगड़ता है। दूसरी तरफ कोविड-19 को लेकर अलग-अलग कारोबारों की प्रतिक्रिया शेयर निवेशकों को अलग-अलग शेयरों के मूल्यांकन का मौका देती है।

क्या केंद्रीय बैंकों ने हालात संभालने के लिए पर्याप्त कदम उठाएं हैं? वैश्विक केंद्रीय बैंकों के रुख पर आपकी क्या राय है? अगले कुछ महीनों में और क्या उम्मीद की जा सकती है?
इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अगर मई के शुरू तक हालात संभल गए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था कमोबेश पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि हालात जून तक ऐसे ही रहे तो समस्याओं से निपटना आसान नहीं होगा। अब ज्यादातर केंद्रीय बैंकों के पास बहुत उपाय शेष नहीं रह गए हैं।

डेट खंडों के लिए आगे की राह कैसी दिख रही है? क्या यह समय डेट में रकम लगाने का है?
कोविड-19 के बाद मची बिकवाली से पहले निवेशक बॉन्ड फंड में रकम डाल रहे थे। कुल मिलाकर मांग की वजह मजबूत है। प्राप्तियां हासिल करने की चाह भी चरम पर है। पिछले सप्ताह जंक बॉन्ड फंड में खासा निवेश आया था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपीय केंद्रीय बैंक मदद करने के लिए उपलब्ध हैं।

मार्च तिमाही में गोल्ड ईटीएफ में 23 अरब डॉलर निवेश

कोरोनावायरस महामारी के बीच निवेशकों द्वारा सुरक्षित दांव अपनाए जाने से सोने में निवेश को बढ़ावा मिला है

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 12 अप्रैल

विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी-मार्च 2020 की तिमाही में स्वर्ण-केंद्रित एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) में 23 अरब डॉलर या 298 टन का शुद्ध निवेश हुआ। यह अमेरिकी डॉलर संदर्भ में सबसे बड़ी तिमाही रकम है और वर्ष 2016 के बाद टन के संदर्भ में सबसे बड़ा आंकड़ा है। डब्ल्यूजीसी ने कहा है, 'पिछले साल के दौरान, गोल्ड ईटीएफ में 659 टन का इजाफा हुआ, जो वित्तीय संकट के बाद से सालाना आधार पर सर्वाधिक है। समान अवधि के दौरान इन ईटीएफ का एयूएम 57 फीसदी बढ़।'

डब्ल्यूजीसी के अनुसार, तेज वृद्धि को कोरोनावायरस महामारी के बीच निवेशकों द्वारा सुरक्षित दांव पर जोर दिए जाने की प्रवृति से बढ़ावा मिला। इस महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है और कई वैश्विक इक्विटी बाजार मंदी के दौर में आ गए हैं तथा सुरक्षित समझी जाने वाली परिसंपत्तियों की मांग बढ़ी है।

आगे की राह

वैश्विक रूप से, गोल्ड ईटीएफ ने मार्च 2020 में 8.1 अरब डॉलर का शुद्ध पूंजी प्रवाह दर्ज किया और 151 टन सोना जोड़ा, जिसके साथ ही इसमें कुल निवेश बढ़कर 3,185 टन के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। डब्ल्यूजीसी ने कहा है, 'कारोबार मात्रा और एयूएम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं क्योंकि सोने में उतार-चढ़ाव बढ़कर वित्तीय संकट के दौरान दर्ज किए गए स्तरों के बराबर पहुंच गया है, लेकिन सोने की कीमतों का प्रदर्शन मार्च में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में काफी हद तक सपाट बना रहा। हालांकि महीने का समापन अपरिवर्तित रूप से 1,609 डॉलर प्रति औंस पर होने के बावजूद मार्च के दौरान सोना अस्थिर रहा। सभी अवधियों में सोने में इस तरह की अस्थिरता का स्तर 2011 में यूरोपीय ऋण संकट के दौरान देखा गया था।'

मार्च 2020 में यूरोपीय फंडों के नेतृत्व में क्षेत्रीय पूंजी प्रवाह 84 टन (414 अरब डॉलर, 5.8 प्रतिशत एयूएम) बढ़ा, जबकि उत्तर अमेरिकी फंडों ने 57 टन (3.2 अरब डॉलर) का सोना जोड़ा।

भारत में गरीबों और विस्थापितों पर पड़ सकती है कोरोनावायरस की बड़ी मार : विश्व बैंक

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 12 अप्रैल

विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 1.5 से 2.8 प्रतिशत कर दिया है। कोविड-19 ने भारत की आर्थिक गतिविधियां पहले ही सुस्त कर दी हैं, ऐसे में आर्थिक विस्तार 1991-92 के भुगतान संतुलन संकट के बाद से सबसे कम रहने के आसार हैं। बैंक ने इसके पहले 2020-21 में भारत की वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।

बैंक ने अपने साउथ एशिया इकोनॉमिक अपडेट में यह भी चेताया है कि विस्थापित मजदूरों और झुग्गी बस्तियों की स्थिति देखकर उन क्षेत्रों में शारीरिक दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करना चुनौतीपूर्ण है, जो कोरोनावायरस के प्रसार के लिए बनाए गए हैं। बैंक ने कहा है कि आर्थिक स्थिति खराब होने का प्रतिकूल असर सरकार की गरीबी कम करने के कार्यक्रम पर भी होगा।

विश्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि औद्योगिक सकल मूल्यवर्धन 2020-21 में स्थिर रहेगा, जो 2019-20 में 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। चालू वित्त वर्ष में सेवा की वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो एक साल पहले 6.9 प्रतिशत थी। वहीं कृषि की वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पहले 3.5 प्रतिशत थी। आईएमएफ भी जल्द ही वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है।

विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि देशबंदी लंबी नहीं खिंचती है तो भातर की आर्थिक वृद्धि 2.8 प्रतिशत रह सकती है। अगर बंदी लंबी चलती है तो वृद्धि गिरकर 1.5 प्रतिशत पर पहुंच सकती है। यह दोनों ही वृद्धि दरें 1991-92 के बाद से सबसे कम होंगी, जब आर्थिक विस्तार गिरकर 1.1 प्रतिशत रह गया था।

कुछ और एजेंसियों ने भी भारत की स्थिति खराब रहने का अनुमान लगाया है। उदाहरण के लिए नोमुरा ने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2020 में 0.5 प्रतिशत सिकुड़ेगी। बहरहाल कुछ अन्य ने इससे बेहतर परिदृश्य भी दिखाया है। उदाहरण के लिए एशियाई विकास बैंक ने उम्मीद की है कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2020-21 में 4 प्रतिशत रहेगी।

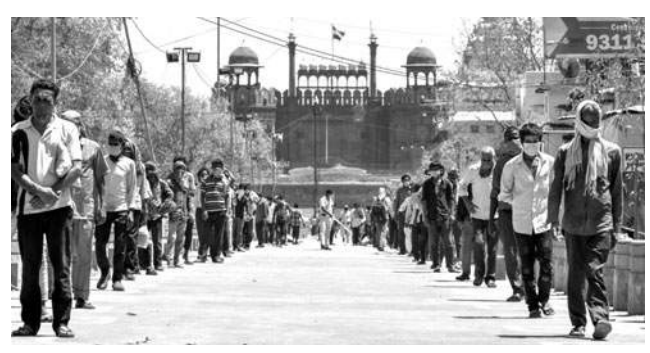

शनिवार को दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा के नजदीक मुफ्त खाना मिलने की आस में लंबी कतार में खड़े लोग -पीटीआई

आर्थिक वृद्धि पर रिपोर्ट

- विश्व बैंक का कहना है कि 1991-92 के भुगतान संकट के बाद पहली बार1.5 से 2.8 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर आ सकती है जीडीपी वृद्धि
- चेतावनी दी कि शारीरिक दूरी बनाए रखना विस्थापित मजदूरों व झुग्गियों में रहने वालों के लिए चुनौतीपूर्ण
- मंदी का भारत की गरीबी घटाने के कार्यक्रम पर होगा असर

बहरहाल विश्वबैंक ने अनुमान लगाया है कि अगले वित्त वर्ष में वृद्धि दर 4 से 5 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो वित्त वर्ष 2019-20 के करीब बराबर या इससे खराब स्थिति होगी।

बैंक ने अनुमान लगाया है कि 2019-20 में जीडीपी वृद्धि 4.8 से 5 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि दूरसे अग्रिम अनुमान में वृद्धि दर 5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। बैंक ने कहा है, 'ढांचागत और वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों के साथ कोविड-19 के कारण आए आर्थिक अवरोधों के कारण वित्त वर्ष 20 में वृद्धि दर 5 प्रतिशत से कम रहने का अनुमान है।' बैंक ने सामान्य राजकोषीय घाटा (केंद्र व राज्यों का मिलाकर) चालू वित्त वर्ष में 9 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान लगाया है क्योंकि सरकारें ज्यादा खर्च करेंगी और राजस्व की आवक कम रहेगी। अगर बंदी लंबी चलती है तो घाटा और ज्यादा हो सकता है। इस संकट से देश की गरीबी घटाने की कवायद पर भी असर पड़ सकता है। बैंक ने कहा है, '2015 में गरीबी में अनुमानित रूप से 13.4 प्रतिशत गिरावट आई थी। वृद्धि सुस्त रहने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था खराब रहने से गरीबी कम करने की कवायद पर विपरीत असर पड़ सकता है।' रिपोर्ट में कहा गया है, 'इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बहुत ज्यादा संक्रामक बीमारी गरीब लोगों के समूहों में बहुत तेजी से फैल सकती है।'

बैंकों के कर्ज की वृद्धि घटी

अभिजित लेले
मुंबई 12 अप्रैल

आर्थिक मंदी और देशबंदी की दोहरी मार झेल रहे बैंकों के कर्ज की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020 में गिरकरक 6.1 प्रतिशत रह गई है, जो वित्त वर्ष 19 में 13.3 प्रतिशत थी। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक जमा में वृद्धि दर भी वित्त वर्ष में कम होकर 7.9 प्रतिशत रह गई है, जो वित्त वर्ष 19 में 10 प्रतिशत थी।

बैंकों को जहां इस पूरे साल मंदी झेलनी पड़ी है, वहीं वित्त वर्ष के अंतिम महीने में कोरोनावायरस की मार पड़ गई। कोरोनावायरस का असर इस वित्त वर्ष में सिर्फ एक महीने रहा, लेकिन वित्त वर्ष 21 में इसका असर ज्यादा नजर आएगा।

भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने वित्त वर्ष 20 में 6 लाख करोड़ रुपये कर्ज दिए हैं, जो वित्त वर्ष 19 के 11.46 लाख करोड़ रुपये से बहुत कम है। 27 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक बकाया कर्ज 103.7 लाख करोड़ रुपये है। बैंकों में वित्त वर्ष 20 में 9.97 लाख करोड़ रुपये जमा हुए, जबकि इसके पहले के वित्त वर्ष में 11.4 लाख करोड़ रुपये जमा हुए थे।

मुश्किल हुआ बड़ा विनिवेश लक्ष्य

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 12 अप्रैल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक विनिवेश लक्ष्य तय किया था। वित्त वर्ष का आरंभ होते ही कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती ने सरकार के भीतर विनिवेश लक्ष्य को पाने पर संदेह के गहरे बादल डाल दिए हैं।

जानकार सूत्रों के मुताबिक सबसे बेहतर स्थिति यह मानी जा रही है कि वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में कोई सौदा नहीं होगा। सबसे खराब स्थिति यह होगी कि सरकार की ओर से निजीकरण के लिए रखे गए दो सबसे बड़े नाम एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम का सौदा इस वर्ष पूरा नहीं हो पाएगा, और सरकार को विनिवेश से होने वाली प्राप्ति लक्ष्य का आंशिक हिस्सा ही मिल सकता है।

कुछ दिनों पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल की अपनी मौद्रिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा था कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था

बड़े विनिवेश लक्ष्य पर संकट

- सबसे बेहतर स्थिति रहने पर भी वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में कोई सौदा नहीं
- सबसे खराब स्थिति होने पर बड़े विनिवेश नहीं हो पाएंगे
- विनिवेश से प्राप्ति लक्ष्य का आंशिक ही संभव
- वित्त वर्ष 2021 के बड़े सौदों में एयर इंडिया, कॉनकॉर, शिपिंग कॉर्प का निजीकरण शामिल
- योजना एलआईसी के आईपीओ की भी
- बीपीसीएल के लिए अभिरुचि पत्र की तारीख बढ़ी

सुस्ती की चपेट में आ सकती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था महामंदी के बाद से सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'यदि कोविड-19 महामारी शीघ्र नियंत्रण में आ भी जाती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाजार को मंदी से उबरने में समय लगेगा। कोई भी विनिवेश सौदा चाहे वह रणनीतिक बिक्री का हो या फिर शेयर बाजार में कोई पेशकश, बहुत जल्दी होने पर अक्टूबर से पहले नहीं होगा।'

कुछ अधिकारी स्वीकार करते हैं कि कोविड-19 महामारी का असर पूरे वर्ष रह सकता है। एक दूसरे अधिकारी ने कहा, 'विमानन क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। ऊर्जा क्षेत्र को भी झटका लगा है। आर्थिक गतिविधि में कमी आने की वजह से पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी आई है।'

एक दूसरे अधिकारी ने कहा, 'हमें देखना होगा कि कब तक ये क्षेत्र पूरी तरह से उबर पाते हैं। इन कारणों का असर एयर इंडिया और बीपीसीएल के लिए इच्छुक खरीदारों की रुचि पर पड़ेगा।'

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्त मंत्रालय का निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) जिन सौदों को गिन रहा था उनमें एयर इंडिया, बीपीसीएल, कॉनकॉर लिमिटेड और शिपिंग कॉर्पोरेशन की रणनीतिक बिक्री और एलआईसी इंडिया लिमिटेड का बहुचर्चित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम शामिल है।

केंद्र की योजना एयर इंडिया में 100 फीसदी हिस्सेदारी, बीपीसीएल में 53 फीसदी हिस्सेदारी, शिपिंग कॉर्पोरेशन में 63.75 फीसदी हिस्सेदारी और कंटेनर कॉर्पोरेशन में 30.8 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की है।

संभावित खरीदारों की तरफ से बीपीसीएल के लिए अभिरुचि पत्र जमा कराने की 2 मई की तारीख को पहले ही बढ़ाकर 13 जून किया जा चुका है। एयर इंडिया के लिए भी इसकी तारीख बढ़ाई जा सकती है। कोविड-19 को देखते हुए दीपम पहले ही संभावित खरीदारों के लिए दस्तावेज जमा कराने के संबंध में कुछ शर्तों को आसान कर चुका है।

एपीएमसी के लिए दिशानिर्देश

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 12 अप्रैल

गुजरात में कृषि उत्पाद विपणन समितियां (एपीएमसी) 14 अप्रैल के बाद मंडी में कामकाज शुरू होने की उम्मीद कर रही हैं, इस बीच गुजरात सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बाजार यार्डों में कोरोनावायरस न फैले। 21 दिन की देशबंदी से अनाज, दलहन, तिलहन का कारोबार बंद रहा है। राज्य के कृषि विपणन एवं ग्रामीण वित्त निदेशक की ओर से राज्य की सभी एपीएमसी को भेजे गए पत्र में कहा गया है, 'लॉकडाउन के दौरान सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि नागरिकों को जरूरी चीजें मिलती रहें। इस समय ज्यादातर अनाज मंडियां बंद हैं। लॉकडाउन के बाद कुछ किसान, थोक और खुदरा कारोबारी अनाज और सब्जियों का कारोबार करने आ सकते हैं, जिससे कोविड-19 के प्रसार की संभावना है। ऐसे में अनाज दलहन और तिलहन के कारोबार के दौरान कुछ अहम कदम उठाने होंगे।' दिशानिर्देशों में शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन, किसानों के आने का अलग-अलग वक्त देना आदि शामिल है।

आटा मिलों का उत्पादन घटकर 25 प्रतिशत पर

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 12 अप्रैल

गेहूं, मजदूर और पैकिंग सामग्री न होने की वजह से देश भर की आटा मिलों ने परिचालन क्षमता औसतन 25 प्रतिशत कम कर दी है। देश भर में 2,500 से ज्यादा छोटी, मझोली और बड़ी इकाइयां हैं, जिनकी कुल सालाना गेहूं पिसाई की क्षमता 2.5 करोड़ टन है। इन मिलों में सूजी, मैदा और आटा तैयार किया जाता है।

छोटी गेहूं प्रसंस्करण इकाइयां, जो कुल मिलों की 50 प्रतिशत हैं, कार्यशील पूंजी रुकी होने के कारण बंद हो गई हैं, जो उन्हें बिस्कुट, ब्रेड और पाव विनिर्माताओं से मिलती है। बंदी के दौरान इस तरह की सभी इकाइयां सार्वजनिक जुटान रोकने के लिए बंद कर दी गईं, जो असंगठित क्षेत्र और कुटीर उद्योगों में आती हैं।

इस तरह से गेहूं के प्रसंस्करण की क्षमता कम होने की वजह से भविष्य में आटा, सूजी, मैदा की आपूर्ति प्रभावित होनी तय है।

महाराष्ट्र के शीरगोन स्थित गेहूं प्रसंस्करण मिल पंचगंगा रोलर फ्लोर मिल्स के डी माणिकचंद ने कहा, 'कुछ मंडियों के बंद होने की वजह से गेहूं खरीद बड़ी समस्या है। साथ ही पुलिसिया उत्पीड़न के डर से ट्रकों की आवाजाही भी प्रभावित है, भले ही सरकार ने अंतरराज्यीय आवाजाही की अनुमति दी है। इसके अलावा पैकेजिंग सामग्री की भी कमी बनी हुई है। इस समय हम क्षमता का महज 25 प्रतिशत काम कर रहे हैं और यही स्थिति देश की सभी छोटी और मझोली इकाइयों की है।'

माणिकचंद ने कहा, 'आटा, सूजी और मैदा जैसे खाद्य पदार्थों को खुला नहीं बेचा जा सकता है, ऐसे में पैकेजिंग सामग्री न मिलने और पैकिंग का कोई विकल्प न होने के कारण उत्पादन घटाना मजबूरी है।'

इसके अलावा 21 दिन की देशबंदी की घोषणा के बाद उल्टी दिशा में विस्थापन हुआ और विनिर्माण क्षेत्र व फ्लोर मिलें इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 अप्रैल को खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर देश भर में आवश्यक जिंस अधिनियम लागू करने को कहा था। इससे स्थानीय अधिकारियों को अधिकार मिल गया है कि वे किसी भी जिंस की स्टॉक सीमा तय कर सकते हैं और किसी भी समय फैक्टरियों व गोदाम की जांच कर सकते हैं। स्टॉक सीमा के दिशानिर्देशों का पालन न होने की स्थिति में 7 साल जेल की सजा हो सकती है। राजस्थान सरकार ने पहले से यह अधिनियम लागू कर दिया है।

रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष संजय पुरी ने कहा, 'हमने सरकार से सिफारिश की थी कि फ्लोर मिल जैसे ग्राहकों को गेहूं की सीधी बिक्री की अनुमति मिलनी चाहिए। साथ ही गेहूं की बंपर पैदावार का अनुमान लगाया गया है और सरकारी एजेंसियां भंडारण केंद्र को लेकर संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में गेहूं खरीदकर खुले में बोरे में रखने से बेहतर है कि फ्लोर मिलों को प्रसंस्करण के लिए गेहूं खरीदकर रखने की मंजूरी दी जाए।'

भारत गेहूं का निर्यात भी करता है। मार्च 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक 275 लाख टन गेहूं भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में पड़ा है। यह पिछले साल के 239 लाख टन भंडारण की तुलना में करीब 15 प्रतिशत ज्यादा है।

बहरहाल कृषि जिंसों के विशेषज्ञ विजय सरदाना ने इस बात पर जोर दिया है कि कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) ऐक्ट में तत्काल संशोधन की जरूरत है, जिससे इसे कारोबारियों के अनुकूल बनाया जा सके।

कोरोनावायरस की देशबंदी में थमा एनसीआर का निर्यात इंजन

शुभायन चक्रवर्ती
नोएडा, 12 अप्रैल

उत्तर भारत की तकलीफदेह गर्मी शुरू होने के पहले ही नोएडा की सड़कें वीरान पड़ गई हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सुनसान सड़क के किनारे आवासीय परिसर खाली हैं। इनमें से अधूरी पड़ी संपत्तियों के कुछ डेवलपरों ने पिछले साल आसपास के प्लॉटों को सरकार को बेचने का फैसला किया था, जहां सरकार ने दो बड़े औद्योगिक केंद्र बनाने की योजना बनाई थी।

पास के ही चाय विक्रेता मनोज ने कहा कि अब मई में निर्धारित तिथि पर इसका उद्घाटन संभव नहीं लगता। उन्होंने कहा कि भवन सामग्री से लदी ट्रकों की यहां कतार लगी रहती थी, जबकि कुछ सप्ताह से सड़कें खाली पड़ी हैं।

नोएडा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस के मुताबिक नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेगा इंडस्ट्रियल जोन की 95 प्रतिशत इकाइयां इस समय बंद हैं।

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिले की उत्तर भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और परिधान निर्यात में बड़ी हिस्सेदारी है। राज्य के कोविड-19 के कुल मामलों में से 58 प्रतिशत से ज्यादा पॉजिटिव मामले इसी जिले से आए हैं।

केंद्र के सबसे बड़े और प्रभावी निर्यात क्लस्टर होने पर गर्व करने वाला यह बड़ा औद्योगिक शहर बड़े घाटे में नजर आ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सिर्फ सरकार द्वारा संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा-एसईजेड में स्थित 274 विनिर्माण इकाइयों में से पिछले मंगलवार को महज 7 चल रही थीं। 310 एकड़ क्षेत्र में फैले इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में रत्न एवं आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर जैसे सेक्टर के

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सहश्र इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्य उत्पादन केंद्र में काम करता एकमात्र कर्मचारी

फोटो-दलीप कुमार

आधार पर सुविधाएं दी गई हैं। सरकार की ओर से बनाए चारों ओर से जमीन से घिरे एसईजेड में से एक इस एसईजेड में बड़े पैमाने पर कम और अर्धकुशल लोगों को रोजगार मिलता है। पिछले साल जनवरी महीने में इस जगह 40,000 से ज्यादा लोग कारोबार करते थे, जिसका सालना कारोबार 90 अरब रुपये था।

और बुरे हुए हालात

अब तक कुछ खुली हुई इकाइयों में से एक सहश्र इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रबंध निदेशक अमृत मनवानी ने कहा, 'इन सभी लोगों की नौकरियां अब जा चुकी हैं। स्थिति को देखते हुए यह कहना बहुत कठिन होगा कि उत्पादन कब तक अधिकतम स्तर पर पहुंच सकेगा और कब तक लॉकडाउन खत्म होगा।' वेंटिलेटर सहित मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माता मनवानी मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। उन्होंने कहा, 'हमने 2 इकाइयों में 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। लेकिन बमुश्किल 20 लोगों की मंजूरी मिली है। अब निर्यात बाध्यताएं पूरी कर पाना बहुत मुश्किल होगा।' उन्होंने कहा कि ढुलाई एक और बड़ी चुनौती है क्योंकि ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय कारोबारी जैसे फेडेक्स और गति अब कह रहे हैं कि कंसाइनमेंट एयरपोर्ट तक पहुंचाएं क्योंकि उनके ट्रकों को सड़कों पर आवाजाही में समस्या हो रही है।

फार्मा, केमिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण की फैक्टरियों को इस समय पूरी तरह छूट है, उसके बावजूद नौकरशाही का संकट बना हुआ है। साथ ही जरूरी प्रमाणपत्र पाने की राह में भ्रष्टाचार के मामले भी आ रहे हैं।

चल रही एक और इकाई के मालिक सुशील कांत गुप्ता ने कहा, 'निश्चित रूप से कोई एकरूपता नहीं है कि प्राधिकारी किस तरीके से जरूरी कारोबार करने के लिए प्रमाणपत्र दे रहे हैं।' एक हफ्ते तक बंदी के बाद उनकी रबर और प्लास्टिक की फैक्टरी फिर से खुल पाई है।

देशबंदी शुरू होने के बाद से ही केंद्र व राज्य सरकार की एजेंसियों की ओर से सरकारी अधिसूचनाओं की बाढ़ आई हुई है और तमाम कारोबारियों तक वह पहुंच नहीं पा रही हैं।

असंख्य मुसीबतें

देश भर में वाटर प्यूरीफायर की आपूर्ति करने वाली केंट आरओ का नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर 59 में मुख्य वितरण केंद्र व कॉर्पोरेट मुख्यालय बंद है। इसके चेयरमैन महेश गुप्ता ने कहा, 'मैंने जिलाधिकारी कार्यालय में अनुरोध किया कि कम से कम सर्विसिंग करने वाले हमारे लोगों को अनुमति दे दी जाए, जिससे खराब हो गए या सही काम नहीं कर रहे वाटर प्यूरीफायरों की मरम्मत की जा सके।'

नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की गलियों में सैकड़ों की संख्या में छोटे कंपोनेंट निर्माता हैं। एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड निर्माता इकाई के प्रबंधक मनोहर कुमार कहते हैं, 'हाल में कई बार बिजली आपूर्ति बाधित हुई। अगर दो डिग्री तापमान भी बढ़ जाता है तो हमारे संयंत्र में भंडारित केमिकल्स बड़ा जोखिम बन सकते हैं। हम उन्हें कहीं हटा नहीं सकते हैं।'

बहरहाल इस अफरातफरी में कुछ सकारात्मक भी हुआ है। देशबंदी में गार्डों और वाचमैन का वेतन अचानक बढ़ गया है। सुनसान औद्योगिक इलाकों में सशस्त्र गार्डों की मांग बढ़ी है, जो औद्योगिक इलाकों में करोड़ों डॉलर के माल की निगरानी कर सकें। लेकिन हर कोई खुश नहीं है। दादरी मेन रोड पर गारमेंट्स से भरे गोदाम की अकेले निगरानी कर रहे सूरजलाल ने कहा, 'मुझे एक सप्ताह के 1,000 रुपये मिलते हैं। पिछले सप्ताह मैनेजर ने 500 रुपये रोज देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक तो एक पैसा नहीं मिला है।'

भारत में गेहूं का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन
2013-14	959
2014-15	865
2015-16	923
2016-17	985
2017-18	999
2018-19	1036
2019-20	1062

उत्पादन लाख टन में
2019-20 के आंकड़े 18 फरवरी 2020 के दूसरे अग्रिम अनुमान
स्रोतः कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि विभाग
बीएस रिसर्च ब्यूरो द्वारा संकलित

बीएस सूडोकू 3713

परिणाम संख्या 3712

		1						
		6			2		7	3
				9		2		
	6		2			1		8
		3						
5	7			3		4		
9			1					6
3								5
					7		8	

1	2	8	7	6	9	5	4	3
9	3	5	1	8	4	2	7	6
7	4	6	3	2	5	9	8	1
3	8	4	5	9	7	1	6	2
5	1	7	2	3	6	4	9	8
2	6	9	4	1	8	3	5	7
8	5	3	9	7	2	6	1	4
4	7	2	6	5	1	8	3	9
6	9	1	8	4	3	7	2	5

कैसे खेलें?

हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मुश्किल

★★★★☆

आर्थिक पैकेज व धीरे-धीरे बाजार खोलने की जरूरत

शुभायन चक्रवर्ती और अभिषेक रक्षित
नई दिल्ली/कोलकाता, 12 अप्रैल

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने आज कहा है कि सरकार को आर्थिक पैकेज की घोषणा करने और मौजूदा देशबंदी खत्म करने के पहले जानकारी देने की जरूरत है। संगठन ने यह भी कहा है कि धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म करने व सुरक्षित तरीके से इससे निकलने की मांग बढ़ रही है।

सीआईआई ने सरकार का समर्थन देते हुए कहा है कि प्रभावित लोगों को नकदी देने के बजाय सीधे राशन देने की जरूरत है। इससे महंगाई बढ़ने को रोका जा सकता है और यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि सरकार का धन बुनियादी जरूरतों पर खर्च किया गया है। उद्योग संगठन ने कहा है कि इस समय लोगों के लिए आश्रय और भोजन दोनों ही मुहैया कराने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'यह व्यवस्था सही नहीं है क्योंकि गलत लोग हमेशा इसका लाभ उठाते हैं। लेकिन यह असाधारण समय है और इसे ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से सही व्यवस्था न होने के बावजूद ऐसा करना होगा।'

वैश्विक महामारी
कोरोनावायरस

सीआईआईने कहा है कि कर्ज वितरण में साल के अंत तक कम से कम 14 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए। सीआईआई ने सभी बैंकों को यह भी सुझाव दिया है कि सभी कंपनियों को उनके 3 महीने के कर्मचारियों के वेतन के बराबर कार्यशील पूंजी 4 से 5 प्रतिशत ब्याज पर दी जानी चाहिए।

चैंबर ने इस बात पर जोर दिया है कि निर्माण, उड्डयन या पर्यटन को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की जरूरत होगी।

सीआईआई ने खनन और धातु क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन पैकेज की मांग की है, जो देशबंदी से प्रभावित हुए हैं। मांग में वित्तीय समर्थन से लेकर नकदी का मसला, लॉजिस्टिक्स और कारोबारी नीति का समर्थन शामिल है।

सीआईआई के एक अधिकारी ने कहा, 'नकदी का मसला हमेशा रहा है, लेकिन इस समय संकट ज्यादा है। लॉकडाउन में कंपनियां कुछ भी नहीं कमा पा रही हैं, जबकि वेतन सहित पहले से नियत खर्चे जारी हैं, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता है।'

सीआईआई ने यह भी कहा है कि धीरे-धीरे उद्योग को प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उद्योग संगठन के मुताबिक जो क्षेत्र आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं वाले हैं, श्रम केंद्रित क्षेत्र हैं और जो भारत के निर्यात बाजार को जिंदा रखने वाले हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चैंबर ने यह भी कहा है कि सरकार उन क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट दे, जिससे जरूरी सामान के आयात कम हो सकें और उनका उत्पादन व निर्यात किया जा सके।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 45

अगला कदम

अब यह लगभग निश्चित हो गया है कि देश के बड़े हिस्से में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि यह निर्णय समझदारी भरा है और जनस्वास्थ्य से जुड़े तमाम लोग इस बात से सहमत होंगे कि देश में कोविड-19 महामारी को सामुदायिक प्रसार के स्तर पर पहुंचने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। सरकार का कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो 15 अप्रैल तक कोविड-19 के मामले 82,000 तक पहुंच सकते थे। यदि लॉकडाउन भी नहीं लगता और रोकथाम भी नहीं होती तो ये 1.20 लाख तक जा सकते थे। परंतु इस मामले पर केवल इसी पहलू से विचार नहीं किया जा सकता है। सरकार को इस बात का खाका तैयार करना होगा कि कैसे एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को आंशिक रूप से शुरू किया जाए और दूसरी ओर इस वायरस के प्रसार को रोका जाए और इसे सफलतापूर्वक ट्रैक किया जाए।

इसमें दो राय नहीं है कि संक्रमण को नियंत्रित रखने में लॉकडाउन की अहम भूमिका रही है। परंतु ज्यादा से ज्यादा जांच और चुनिंदा ढंग से पृथकवास की व्यवस्था भी कारगर साबित हुई है। देश में जांच का दायरा बहुत अधिक सीमित है और ऐसे में इन आंकड़ों को बहुत अधिक विश्वसनीय मानते हुए इनके आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। पॉजिटिव मामलों की वृद्धि दर में अवश्य बदलाव आया है। मार्च के तीसरे सप्ताह तक संक्रमित लोगों की तादाद हर तीसरे दिन दोगुनी हो रही थी। अब इसमें ज्यादा समय लग रहा है। हालांकि इसे संक्रमण की वास्तविक स्थिति का अक्स नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसके लिए जांच को अत्यधिक सघन और तेज करने की आवश्यकता होगी। सरकार को इस दिशा में प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

यह बात ध्यान देने वाली है कि व्यापक लॉकडाउन सरकार के तरकश का इकलौता तीर नहीं है। कुछ पूर्वी एशियाई देशों ने जांच का दायरा बढ़ाकर और पृथक्करण और संपर्कों की पड़ताल के माध्यम से महामारी के प्रसार को प्रभावी तरीके से रोका है।

अलग-अलग देशों में नतीजों में काफी अंतर रहा है। एक ओर जहां सैन फ्रांसिस्को ने न्यूयॉर्क से पहले लॉकडाउन किया या आयरलैंड ने ब्रिटेन से पहले लॉकडाउन किया। इसका इन शहरों में बीमारी के प्रसार पर भी असर दिखा। दूसरी ओर, ऑस्ट्रिया या डेनमार्क जैसे देशों ने लॉकडाउन समाप्त करना शुरू कर दिया है। वायरस जर्मनी की तुलना में इटली में अधिक घातक साबित हुआ। यह स्पष्ट नहीं है कि विभिन्न भूभाग में यह अंतर क्यों आ रहा है। सरकार को नियंत्रण और प्रसार को लेकर अन्य तौर तरीकों पर भी विचार करना चाहिए।

यह तय है कि लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने की योजना आवश्यक है। इसके साथ-साथ संक्रमण और एंटीबॉडीज (पुराने संक्रमण से संबंधित) का पता लगाने के लिए व्यापक जांच की भी आवश्यकता है। संक्रमित लोगों से संपर्क में आने वालों का पता लगाने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। ऐसा करके हॉटस्पॉट का जल्द पता लगाया जा सकता है। यह पता लग जाने पर कि वायरस कहां तेजी से फैल रहा है, उसके अनुसार योजना बनाई जा सकती है जो उन इलाकों और वहां संक्रमितों से संपर्क में आने वालों का पृथक्करण करने या प्रतिबंधित करने से संबंधित हो। परंतु इसके लिए भी सघन जांच प्राथमिक शर्त है। उस स्थिति में शेष अर्थव्यवस्था को खोला जा सकता है। केवल लॉकडाउन बढ़ाना समझदारी नहीं होगी। यह स्पष्ट है कि अभी भी सरकार को काफी कुछ करना है। खासतौर पर जांच बढ़ाने के क्षेत्र में काफी अधिक सुधार करना होगा।

विनय सिन्हा

बीच का रास्ता ही होगा कारगर

लॉकडाउन कारगर रहा है। परंतु इसे लंबा खींचने के अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसमें व्यवस्थित तरीके से रियायत देनी चाहिए।

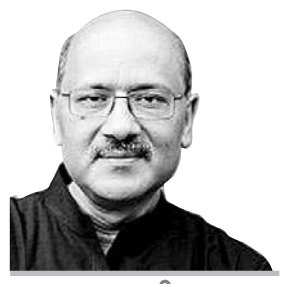

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो ने भारत से हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासिटामॉल की मांग करते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और रामायण में लक्ष्मण का जीवन बचाने के लिए हनुमान के संजीवनी बूटी लाने के प्रसंग का जिक्र किया तो वह शायद ही जानते हों कि वह ऐसा कितने उपयुक्त समय पर कर रहे हैं। शायद उनके कार्यालय में कोई पक्का हनुमान भक्त है जिसने यह सुनिश्चित किया कि यह पत्र ठीक हनुमान जयंती के दिन यहां पहुंचे। चाहे जो भी हो, आज जब हम तीन सप्ताह के लॉकडाउन को आगे बढ़ाने (आशा है ऐसा न हो), पूरी तरह समाप्त करने (हम ऐसा भी नहीं चाहते) या व्यवस्थित छूट देने की बात पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें ऐसी तमाम कहानियां याद आ रही हैं। हम इनमें से तीसरे विकल्प को प्राथमिकता देंगे बेशक बजरंगबली की मदद से। हमारे देवता केवल दयालु ही नहीं हैं बल्कि उनमें हास्यबोध भी है। खासकर उनमें जिनका जिक्र बोल्सोनारो ने किया।

हनुमान को याद कीजिए। लक्ष्मण अचेत पड़े हैं, उन्हें रावण के पुत्र मेघनाद जिसे इंद्रजित के नाम से भी जाना जाता है, ने आज के जमाने के हिसाब से किसी आधुनिक नियंत्रित शस्त्र से घायल किया है। लंका के बेहतरीन चिकित्सक सुषेण कहते हैं कि हिमालय की जादुई औषधि संजीवनी बूटी ही उन्हें बचा सकती है। जामवंत कहते हैं कि केवल हनुमान ही वह बूटी ला सकते हैं।

इसके बाद की कथा हमें मालूम है। बूटी को पहचानने में विफल हनुमान समूचा द्रोणागिरि पर्वत ही उठा लाए। हनुमान से जुड़ी कथाओं में यह अत्यंत चर्चित है। सुषेण ने तत्काल बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया।

यह बात मौजूदा हालात पर भी लागू होती है। आईसीएमआर ने फरवरी के मध्य में देश में कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में इजाफे की निगरानी शुरू की। शुरुआत में लक्षण वाले संदेहास्पद, विदेश से लौटने वाले या उनके संपर्क में आने वाले लोगों का परीक्षण किया गया। यह तादाद बेहद कम थी। प्रति 10 लाख परीक्षण के मानक पर भी यह बेहद कम था। आईसीएमआर के विशेषज्ञों ने देश में महामारी विज्ञान के सबसे पुराने और प्रचलित तरीके को अपनाया।

इसमें उन रोगियों के नमूने लिए गए जो सांस के गंभीर संक्रमण से ग्रस्त थे या जो गंभीर निमोनिया से पीड़ित होकर 50 बड़े अस्पतालों के आईसीयू में थे। शुरुआती दो सप्ताह में जो 826 नमूने लिए गए उनमें से एक भी कोविड-19 संक्रमित नहीं था। इसे इस बात का प्रमाण माना गया कि यह बीमारी अभी पहले और दूसरे चरण में है। यानी यह या तो विदेशों से आने वालों में है या उनके संपर्क में आने वालों में।

बाद के दिनों में जब जांच बढ़ी तो 19 मार्च को दो पॉजिटिव मामले सामने आए। अब तक के 965 नमूनों में से दो। किसी ने मुझसे कहा नहीं है लेकिन जितना मैं इस व्यवस्था को जानता हूं उसके हिसाब से यह खतरे की घंटी थी। उसी दिन देश भर के सभी अस्पतालों में सांस के गंभीर संक्रमण वाले मरीजों की जांच की घोषणा की गई। अगले दो सप्ताह में यानी 2 अप्रैल तक 4,946 जांच की गई।

आईसीएमआर की पिछले दिनों प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया कि सांस के गंभीर संक्रमण वाले 5,911 मामलों में 104 कोरोना पॉजिटिव निकले। यह अभी भी मात्र 1.8 फीसदी था लेकिन नगण्य ही। 21 से 23 मार्च के बीच यह स्थिति बन चुकी थी। इससे समझा जा सकता है कि कैसे लॉकडाउन की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। अब लक्षित हल तलाश करने का समय नहीं रह गया था। संक्षेप में कहें तो अब जड़ी बूटी पहचानने का नहीं बल्कि सीधे पहाड़ उठा लेने का वक्त था। इसके पश्चात क्या उस पहाड़ के समक्ष बैठकर तीन सप्ताह का वक्त काटा जाता? ऐसा करने पर तो लक्ष्मण की जान ही जोखिम में आ जाती। लक्ष्मण यानी अर्थव्यवस्था और देश का गरीब तबका मरणासन्न हो रहा था। हमें किसी ऐसे ज्ञानी की आवश्यकता है जो जरूरी बूटी तलाश करे या कम से कम ऐसी बूटियों का समूह जो कारगर हों।

तमाम वैश्विक आकलन सामने आए हैं जिनमें कहा गया है कि भारत का लॉकडाउन इस महामारी को लेकर सबसे तीक्ष्ण प्रतिक्रिया है। सबसे उल्लेखनीय है द इकनॉमिस्ट द्वारा प्रयोग किया गया ग्राफिक। यह ग्राफिक ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय के ब्लावत्नीक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट द्वारा तैयार किया गया है। भारत 100 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर है जबकि इटली 90 प्रतिशत पर। परंतु यही सूचकांक हमारी सीमाएं भी दिखाता है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन की बात करें तो भारत चार्ट में सबसे नीचे है।

इसे समझना मुश्किल नहीं है। सूचकांक में जितने भी देश शामिल हैं उनमें भारत सबसे गरीब है। भारत के बाद जो गरीब देश हैं वे उतने भी गरीब नहीं है। चीन और मलेशिया दोनों का प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से पांच गुना है। भारत के सामने तिहरी चुनौती है। भारत भीड़ भरा देश है, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और वह गरीब है। इन हालात में व्यापक लॉकडाउन आवश्यक था। परिणाम बताते हैं कि यह कारगर रहा है। जांच का दायरा बढ़ने के साथ संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। परंतु ग्राफ में गुणात्मक वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है।

कुछ तो कारगर रहा है। बीसीजी से लेकर क्लोरोक्वीन तक या हमारी जीन संरचना तक क्या कारगर रहा है इस बारे में बात हो सकती है लेकिन लॉकडाउन का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। ऐसे में स्वाभाविक मांग इसे आगे बढ़ाने की होगी। कई राज्यों की सरकारें ऐसी मांग कर चुकी हैं। कुछ राज्य इसे बढ़ा भी चुके हैं।

क्या यह कारगर होगा? या फिर यह दवा के उस ओवरडोज की तरह होगा जो अल्पावधि में जीवन रक्षक है लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से नुकसान करती है?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले दिनों रोकथाम के लिए जो योजना सामने रखी उससे कुछ बातें निकलती हैं। करीबी नजर डालें तो पता चलता है कि राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल कारगर है जिसे व्यापक भौगोलिक प्रसार और अलग-अलग जगहों की जरूरतों के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है।

ऐसे में पूरे देश को लॉकडाउन करने के बजाय भीलवाड़ा जैसी जगहों को पहचान कर उनके चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच दी जाए। दिल्ली समेत कुछ राज्यों में चिह्नित इलाकों को हॉटस्पॉट और रोकथाम क्षेत्र घोषित भी किया गया है।

हमें इस मॉडल को अपनाना चाहिए। यह एकबारगी लॉकडाउन की घोषणा करने से कहीं अधिक मुश्किल काम है। परंतु लॉकडाउन को तीन सप्ताह से आगे बढ़ाना काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तमाम लोग रोज कमाने और खाने वाले हैं। रबी की फसल कटाई और भंडारण की राह देख रही है। खेतों को खरीफ के लिए तैयार किया जाना है। फैक्टरियों को अपना काम शुरू करना है। इनमें दवा फैक्टरियां भी शामिल हैं। जहां कहीं भी चुनौती है, वहां रोकथाम का मॉडल अपनाया जाए।

वेंटिलेटर खरीदने पर काफी जोर है लेकिन हमें यह क्रूर सच समझना होगा कि वेंटिलेटर पर पड़े मरीज का क्या हाल होता है। पिछले दिनों व्हाइट हाउस में प्रेस से बातचीत में डॉनल्ड ट्रंप ने वेंटिलेटर से जुड़े एक सवाल पर कहा था कि क्या आप मुझसे यह पूछना चाहते हैं कि वेंटिलेटर पर जाने वाले लोगों में से कितनों की जान बचती है? आप नहीं जानना चाहेंगे।

परंतु एक दिन पहले न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने गलती से ही सही लेकिन इसका जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि वेंटिलेटर पर गए मरीजों में से केवल 20 फीसदी ही जीवित बचते हैं। बेहतर यही होगा कि मरीजों को वेंटिलेटर पर जाने से पहले बचा लिया जाए।

यहां हमने 1.38 अरब की पूरी आबादी और 3 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। अब वक्त आ गया है कि मरीज को आंशिक रूप से ही सही खुद सांस लेने दी जाए।

मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर सकता है कोविड-19

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

> कोरोनावायरस की महामारी से लड़ना और निपटना केवल शारीरिक या स्वास्थ्यगत चुनौती नहीं है बल्कि यह मनोवैज्ञानिक चुनौती भी है।

कई लोगों के लिए यह एक अनजानी अनिश्चितता का डर है कि उन्हें कितने दिन तक अपने रोजमर्रा के कामकाज को स्थगित रखना पड़ेगा। कई अन्य को आशंका है कि कहीं वे कोरोनावायरस के संपर्क में न आ जाएं या फिर कहीं यह उनकी वित्तीय हालत को नुकसान न पहुंचाए। परंतु बात केवल इतनी नहीं है। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिनको आशंका है कि उनका रोजगार छिन सकता है। इसके बाद एक बड़ी चिंता यह है कि लोगों के वेतन में कटौती हो सकती है।

दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 संकट ने आर्थिक और वित्तीय अस्थिरता का एक मिश्रण तैयार किया। इसमें दो राय नहीं कि मौजूदा आशंकाएं सच हैं। लोगों के सामान्य जीवन में भारी उथलपुथल उत्पन्न हो गई है। जाहिर है इसका असर लोगों के भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। उदाहरण के लिए लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में लोगों ने घबराहट में किराने की जमकर खरीदारी कर ली। यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे अस्थिरता और अनिश्चितता की आशंका में लोग अजीबोगरीब व्यवहार करने लगते हैं। हकीकत में संक्रमित होने का खतरा कई लोगों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की आशंका पैदा कर चुका है।

सबसे बड़ी आशंका यह है कि यह महामारी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। यह कई तरीके से हो सकता है। उदाहरण के लिए घर से काम करना जो शुरुआती दिनों में वरदान प्रतीत हो रहा था वह धीरे-धीरे अरुचिकर प्रतीत होने लगा है। एक आशंका तो यह है कि लगने लगेगा कोई काम है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर लोगों में ज्यादा काम करने की प्रवृत्ति पैदा होने लगी है। उन्हें लगने लगा है कि उन्हें लंबे समय तक काम करना चाहिए ताकि वे अपने सहकर्मियों और बॉस को दिखा सकें कि वे काम करते समय दूसरों की तुलना में अधिक उत्पादक रह सकते हैं। जब लोग घर से काम करते हैं और समय पर कोई फोन नहीं उठा पाते या ईमेल का जवाब नहीं दे पाते तो सहकर्मियों को ऐसा लग सकता है कि वे काम को गंभीरता से ले भी रहे हैं या नहीं। आम जीवन में तनाव सामान्य बात है। परंतु एक बात जिसने जाने-अनजाने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया है वह यह है कि वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक विसंगतियों में नोवेल कोरोनावायरस ने लाखों लोगों को भौतिक रूप से शेष दुनिया से अलग-थलग कर दिया है। भविष्य के अज्ञात भय के साथ मिलकर यह बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी के मुताबिक शारीरिक दूरी, पृथक्करण के उपाय, स्कूलों और कार्यालयों का बंद होना आदि कदम खासतौर पर चुनौती भरे हैं। क्योंकि ये कदम उन कामों को प्रभावित करते हैं जो हमें पसंद हैं, हमारे साथियों को हमसे दूर करते हैं।

अकेलापन दुनिया के सबसे महत्त्वपूर्ण जोखिमों में से एक है। अब जबकि अनेक लोगों की आजादी से घूमने फिरने की गतिविधियों पर अंकुश लग गया है तो समस्या और बिगड़ गई है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए जिनका सामाजिक जीवन भी सीमित है। यहां डिजिटल युग हमारी सहायता कर सकता है। आखिरकार इससे पहले कभी अपने प्रिय लोगों से जुड़ा रहना इतना आसान नहीं रहा। कम से कम वीडियो कॉल के माध्यम से करीब होने का भ्रम तो होता है। ऐसा लगता है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वे हमारे आसपास हैं।

इस पृथक्करण का लाभ लेने का एक तरीका यह है कि हम उन चीजों की प्राथमिकता तय कर सकते हैं जो हमें पसंद हैं लेकिन जिनके लिए हम अब तक समय नहीं निकाल पा रहे थे। इस एकाकीपन को दूर करने के लिए लोगों को अपने जीवन के उन पहलुओं पर विचार करना चाहिए जिन पर वे अब तक ध्यान नहीं दे पाए थे।

मनोवैज्ञानिक जो सलाह दे रहे हैं उनमें से एक यह है कि कोविड-19 के बारे में कम से कम खबरें देखें, सुनें या पढ़ें क्योंकि वे हमें निराश करती हैं। बस दिन में एक या दो बार इसके बारे में जानकारी जुटाएं। अचानक इस बीमारी के बारे में खबरों की बाढ़ किसी को भी चिंतित कर सकती हैं।

इस समय बच्चों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। बच्चे संवेदनशील हैं और जब वे बड़ों को निराशाजनक ढंग से वायरस के बारे में बात करते देखते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं। इसका आगे चलकर उनके मनोविज्ञान पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

अंत में, अब जबकि कोविड-19 के बाद छंटनी और वेतन कटौती अपरिहार्य है तो ऐसे में कंपनियों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी ताकि वे इससे उपजे तनाव से निपट सकें। इससे निपटने के तरीके को जितना पारदर्शी रखा जाए उतना ही अच्छा। हर कोई इसकी वजह से परिचित है लेकिन सभी चाहते हैं कि उनके साथ सम्मान से और समानुभूति से पेश आया जाए। संस्थान से बाहर जा रहे लोगों के साथ आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उसे संस्थान के बाकी लोग बहुत गौर से देखते हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोनावायरस की महामारी से लड़ना और निपटना केवल शारीरिक या स्वास्थ्यगत चुनौती नहीं है बल्कि यह मनोवैज्ञानिक चुनौती भी है।

कानाफूसी

बदले की भावना!

पिछले दिनों पाकिस्तान कोविड-19 के मसले पर आयोजित क्षेत्रीय व्यापार अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि इसकी मेजबानी भारत को नहीं करनी चाहिए थी बल्कि इसका आयोजन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) सचिवालय द्वारा किया जाना चाहिए था। पाकिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देशों के व्यापार अधिकारी इसमें शामिल हुए और अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर कोविड-19 के असर तथा यात्रा प्रतिबंधों को लेकर चर्चा की। वहां इस बात पर सहमति बनी कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार के नए स्थायी तरीके तलाश करने होंगे क्योंकि यह महामारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह क्षति पहुंचा रही है। इस बैठक के पहले 15 मार्च को सार्क देशों के नेताओं की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजित कराया था। उस बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सहायक डॉ. जफर मिर्जा शामिल हुए थे। पाकिस्तान को लगता है कि सार्क को तालमेल के साथ काम करना चाहिए। अब उसने इसी विषय पर सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान को इसमें शामिल होने का न्योता नहीं है। पाकिस्तान को भारत के कोविड-19 फंड स्थापित करने के सुझाव से भी आपत्ति है। पाकिस्तान के अलावा सभी देशों ने इसमें सहायता देने की बात कही है। पाकिस्तान का कहना है कि इसे सार्क के महासचिव के नियंत्रण में रखा जाए और इसके उपयोग की पारदर्शी व्यवस्था हो। भारत ने 2016 में पाकिस्तान द्वारा आयोजित एक सार्क बैठक को नाकाम किया था। लगता है पाकिस्तान भूला नहीं है।

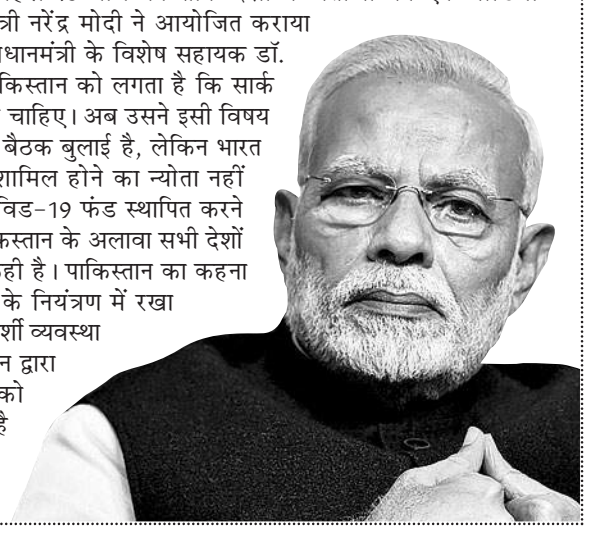

आपका पक्ष

चीन में सामान्य होते हालात का यहां प्रभाव!

दुनिया भर में तबाही मचा रहे कोरोनावायरस को लेकर बहुत दिन बाद कुछ अच्छा सुनने को मिला है। खबर है कि वुहान शहर समेत पूरा चीन अब कोरोनावायरस के चंगुल से निकल गया है। वुहान में कोरोना के मामले नहीं आ रहे हैं। इसी आधार पर वुहान में 76 दिनों से चल रहा लॉकडाउन हटा लिया गया है। भारत में अभी हालात खराब हैं। यहां कोरोना संक्रमण से संबंधित रोजाना लगभग 500 नए मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत आयात के मामले में चीन पर आश्रित रहा है। शीर्ष 20 उत्पादों में से जो भारत दुनिया से आयात करता है, चीन उनमें से अधिकांश में एक महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक आयात यानी लगभग 45 प्रतिशत चीन पर निर्भर है। लगभग एक-तिहाई मशीनरी जिन्हें भारत आयात करता है, वे चीन से ही आती हैं। मोटर वाहन क्षेत्र और उर्वरकों के लिए भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से अधिक है। लगभग 65 से 70 प्रतिशत सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री और लगभग 90 प्रतिशत मोबाइल फोन चीन से भारत में आते हैं। चीन से आयात किया जाने वाला कच्चा माल और हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वो सभी जरूरी सामान जो चीन से आयात करते हैं, वे हमारे बाजार की सबसे बड़ी जरूरत है। साथ ही भारत में लगभग सभी जेनेरिक दवाओं को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल के आयात को लेकर भी हम चीन पर ही निर्भर रहते हैं और आपदा की इस घड़ी में हम महत्त्वपूर्ण दवाओं के लिए भी हम चीन पर निर्भर हैं। चीन में स्थिति सामान्य होते ही भारत बड़े पैमाने पर इन उपयोगी वस्तुओं का रणनीतिक स्तर पर आयात प्रारंभ करेगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र के लिए चीन पर हमारी निर्भरता किसी से छिपी नहीं है।

आकाश सिंह, प्रयागराज

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण किया

लॉकडाउन-2 में और ज्यादा गंभीर हों

कोरोना को हराने के लिए पहले का 21 दिन का लॉकडाउन कुछ खास कामयाब नहीं रहा, क्योंकि इस दौरान कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगभग 8,000 हो गया है। सबसे पहले तो यह सवाल उठता है कि जब देश में 21 दिन का लॉकडाउन था तो कोरोना के मरीजों की संख्या क्यों बढ़ती गई। अब कुछ राज्य लॉकडाउन लगभग 15 दिन और बढ़ाने की सोच रहे हैं। लेकिन यह तभी कामयाब होगा जब सरकारें, प्रशासन और आम लोग ओर ज्यादा सख्ती से इसके प्रति गंभीर होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार को आगे लॉकडाउन बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह कदम देश के बहुत से क्षेत्रों और विकास कार्य के लिए नुकसानदेह होगा। सभी को यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकार और प्रशासन लॉकडाउन-2 में कुछ ढील भी देते हैं तो उनका किसी को नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी लापरवाही संक्रमण को बढ़ा सकती है। सरकार को डॉक्टर, नर्स और मरीजों का इलाज कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

कोरोनावायरस से वस्त्र उद्योग को भारी नुकसान

विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से नए ऑर्डर और उत्पादन बंद, लॉकडाउन से पहले भेजी गई खेपों के भुगतान में भी हो रहा विलंब

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 12 अप्रैल

देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल केंद्रों में से एक तिरुपुर की व्यस्त रहने वाली सड़कें मौजूदा समय में सुनसान दिख रही हैं। यहां 10,000 फैक्टरियों (मुख्य तौर पर छोटे एवं मझोले उद्यम) में कामकाज ठप है। इन फैक्टरियों में 600,000 से ज्यादा लोग काम करते थे। यह शहर लगभग 25,000 करोड़ रुपये के निर्यात के लिए जाना जाता है और करीब इतना ही योगदान उसका घरेलू बाजार में है। अब इस शहर को महज तीन महीने में 10,000-12,000 करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका है।

तिरुपुर की स्थिति लॉकडाउन के बाद से अन्य प्रमुख टेक्सटाइल क्षेत्रों की तरह ही है। कृषि के बाद, दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता टेक्सटाइल उद्योग मौजूदा दौर में अपनी 25 प्रतिशत नौकरियों का नुकसान दर्ज कर सकता है। लगभग 1.29 लाख लोगों की आजीविका इस उद्योग पर निर्भर है और इनमें करीब 70 प्रतिशत महिलाएं हैं।

जहां कोविड-19 महामारी से पूरी तरह उत्पादन ठप हो गया है और नए ऑर्डर प्रभावित हुए हैं, वहीं निर्यातकों का कहना है कि लॉकडाउन से पहले भेजी गई खेपों के भुगतान में भी विलंब हुआ है। निर्यातकों का कहना है कि कुछ ग्राहक इसलिए खेपों की डिलिवरी नहीं ले रही हैं क्योंकि उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। रेडीमेड गारमेंट कंपनियों को चीन में मांग सुधरने से उम्मीद दिख रही है, लेकिन कोरोनावायरस यूरोप, अमेरिका और अन्य प्रमुख बाजारों में तेजी से फैल रहा है, जिससे रिटेलरों से नए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। यह सही है कि सरकार ने इन कंपनियों की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने और तरलता को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र करों पर छूट 1 अप्रैल से आगे बढ़ा दी है, लेकिन इससे उन कई खरीदारों को मदद नहीं मिलेगी जो लॉकडाउन की वजह से कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं और स्टोरों के लगातार बंद होने से निर्यात में गिरावट आई है।

इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2020 के लिए, मार्जिन 120-150 आधार अंक तक प्रभावित होने और तरलता पर दबाव से क्रेडिट मानक कमजोर रहने की आशंका है। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि भारत का निर्यात (जो अमेरिका-चीन व्यापारिक टकराव की वजह से जनवरी 2020 तक पहले ही 40 प्रतिशत तक घट चुका है) वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही तक प्रभावित रहेगा। एजेंसी का कहना है कि पूरे टेक्सटाइल पोर्टफोलियो में एबिटा में कम से कम 15 प्रतिशत की कमी आएगी।

- यूरोप, अमेरिका और अन्य प्रमुख बाजारों में तेजी से फैल रहा कोरोनावायरस
- खुदरा कारोबारियों की ओर से नहीं मिल रहे नए ऑर्डर
- मूल्य के हिसाब से देश के कपड़ा निर्यात में परिधान क्षेत्र का योगदान 43 प्रतिशत और कुल निर्यात में हिस्सेदारी 5 प्रतिशत

घरेलू टेक्सटाइल उद्योग में खेपें रुक गई हैं और अल्पावधि परिचालन पुन: शुरू होने को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। कुछ बड़ी कंपनियों के पास बुरे समय से निपटने के लिए पर्याप्त नकदी मौजूद है, लेकिन यदि कोरोनावायरस का प्रभाव अनुमान से ज्यादा समय तक बना रहा तो छोटी कंपनियों के लिए दुखद परिणाम सामने आएगा। मॉल और शॉपिंग केंद्र बंद रहने, आवाजाही प्रतिबंधित किए जाने, और परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से घरेलू बिक्री प्रभावित हुई है। भारत ने 2018-19 में 16.2 अरब डॉलर मूल्य के गारमेंट का निर्यात किया था। अपैरल सेक्टर का भारत के टेक्सटाइल निर्यात में वैल्यू के संदर्भ में 43 प्रतिशत और कुल निर्यात में 5 प्रतिशत का योगदान है।

रिटेल के जरिये निर्माण समेत पूरे गारमेंट उद्योग में करीब 2.5 लोग काम करते हैं। क्लोदिंग मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के अनुसार यदि मौजूदा हालात एक महीने के बाद भी बने रहे तो इस उद्योग में लगभग एक-चौथाई रोजगार समाप्त हो जाएगा। सीएमएआई का मानना है कि हालात सुधरने में कम से कम 10 महीने से लेकर एक साल का वक्त लगेगा। संगठन का कहना है कि सरकारी सहयोग के बगैर यह उद्योग इस कठिन दौर में अपना अस्तित्व बचाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएगा।

राजस्थान के भीलवाड़ा को 25,000 करोड़ रुपये मूल्य के पीवी सूटिंग्स और डाइड यार्न के लिए प्रमुख केंद्र के तौर पर जाना जाता था। अब यह कोरोनावायरस का हॉटस्पॉट बन गया है। राजस्थान टेक्स्टाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन एवं भीलवाड़ा में संगम के प्रबंध निदेशक एस एन मोदानी का कहना है कि इस शहर में टेक्सटाइल उद्योग लगभग 35,000 करोड़ रुपये का है जिसमें निर्यात भी शामिल है।

21 मार्च की रात से भीलवाड़ा में गतिविधि ठप हो गई है। यदि उद्योग 14 अप्रैल के बाद परिचालन पुन: शुरू करने में सफल रहा तो भी राजस्व को सालाना आधार पर 15-20 प्रतिशत नुकसान होने की आशंका है। निर्धारित खर्च की वजह से मुनाफे पर भी दबाव पड़ेगा। यदि लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो नुकसान और बढ़ जाएगा।

राजस्थान से कुल निर्यात लगभग 10,000 करोड़ रुपये का है। बंदरगाहों से मंजूरी नहीं मिलने, सीमाओं के सील होने और ग्राहकों द्वारा ऑर्डर रद्द किए जाने से 25 प्रतिशत व्यवसाय पहले ही समाप्त हो चुका है।

तिरुपुर निर्यातक संघ के अध्यक्ष राजा एम षणमुगम ने कहा, 'खासकर इटली और स्पेन से यूरोपीय खरीदार हमारे सदस्यों से गारमेंट निर्यात नहीं करने और कम से कम एक या दो महीने तक इंतजार करने को कह रहे हैं।' उन्होंने कहा कि छोटे एवं मझोले उद्यमी मौजूदा हालात में बैंक ऋण अदायगी में सक्षम नहीं होंगे। षणमुगम का कहना है, 'हमें यह आशंका सता रही है कि बकाया न मिलने की वजह से बैंक कहीं इस तरह की इकाइयों को बेसेल मानकों के तहत एनपीए परिसंपत्तियां घोषित न कर दें।' कुल मिलाकर, अब इस उद्योग की कंपनियां कोरोना प्रभाव कम होने और उसके बाद मांग सुधरने का इंतजार कर रही हैं।

आलू का भंडारण इस साल 15 फीसदी कम

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 12 अप्रैल

इस साल देश में आलू का भंडारण कम होने का अनुमान है। इसकी वजह आलू की कम पैदावार और कोरोना के कारण पैदा हुई स्थिति है। इस समय आलू महंगा बिक रहा है। कम भंडारण और पिछले साल से दोगुने ज्यादा भाव पर भंडारण होने के कारण इस साल आगे भी इसके सस्ता होने की संभावना नहीं दिख रही है,बल्कि पिछले साल की तुलना में महंगा ही बिकने के आसार हैं।

फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजेश गोयल बताया कि पिछले साल देश में भंडारण क्षमता के मुकाबले 78 फीसदी आलू के कोल्ड स्टोर भरे थे। इस साल 62 से 65 फीसदी कोल्ड स्टोर ही भरे हैं। देश में 40 से 45 करोड़ कट्टा यानी 50 किलोग्राम आलू का भंडारण होने का अनुमान है। गोयल ने कहा कि कम आलू लगने से इसका उत्पादन 3 से 4 फीसदी घटने का अनुमान है, जिसका असर आलू के भंडारण पर भी हुआ है। इसके अलावा लॉकडाउन के बीच आलू की फसल में देरी से भी भंडारण में कमी आई है। हालांकि लॉकडाउन के बीच सरकार के सहयोग और कोल्ड स्टोर संचालक व मजदूरों दवारा बीमारी की चिंता किए बिना की गई मेहनत से खपत लायक भंडारण हो गया है। आलू भंडारण के प्रमुख केंद्र आगरा की कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुदर्शन सिंघल ने कहा कि आगरा में पिछले साल की तुलना में 10 फीसदी कम आलू का भंडारण हुआ है। हर साल 15 मार्च तक आलू कोल्ड स्टोर में चला जाता था। लेकिन इस साल फसल में देरी और लॉकडाउन के कारण इस सप्ताह तक आलू का भंडारण होता रहा।

इस साल आगे भी आलू महंगा बिकने की संभावना है। सिंघल ने कहा कि आलू का भंडारण 12 से 15 रुपये किलो भाव पर हुआ है। भंडारण किराया व अन्य खर्चों को मिलाकर भंडारण वाले आलू की लागत 15 से 18 रुपये किलो बैठती है। ऐसे में भंडारण वाला आलू 20 रुपये किलो से कम बिकने पर किसान और भंडारण करने वाले कारोबारियों को नुकसान होगा। गोयल ने कहा अभी तक मंडियों में किसानों के खेतों में रखे आलू की आवक हो रही है। आगे कीमतों के बारे में गोयल कहते हैं कि भले ही आलू का भंडारण पिछले साल से कम हुआ हो, लेकिन खपत के लिए पर्याप्त आलू स्टोरों में उपलब्ध है। हालांकि ऊंचे भाव पर भंडारण होने के कारण आगे आलू की कीमतें तेज रहने की ही संभावना है, क्योंकि दाम गिरने पर भंडारणकर्ताओं को नुकसान होने लगेगा।

आगरा मंडी में इस समय आलू 12 से 15 ररुपये किलो के भाव पर बिक रहा है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू की कीमत 12 से 19 रुपये किलो है। देश भर के खुदरा बाजारों में आलू 30 से 45 रुपये किलो बिक रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान देश में 501 लाख टन आलू पैदा हुआ है।

बासमती की कीमतें बढ़ीं, निर्यात घटा

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 12 अप्रैल

- कोविड-19 महामारी से भारतीय बासमती निर्यात प्रभावित हुआ है
- घरेलू बाजार में बासमती कीमतें मजबूत बनी हुई हैं
- लॉकडाउन हटने के बाद कारोबार सामान्य होने में 6-7 सप्ताह लगेंगे

कोरोनावायरस महामारी से भारतीय बासमती चावल निर्यात प्रभावित हुआ है। ईरान और अन्य खाड़ी देशों के लिए निर्यात खेपों को रद्द किए जाने का संकट पैदा हो गया है, हालांकि मौजूदा लॉकडाउन की अवधि के दौरान घरेलू कीमतों में कुछ हद तक मजबूती आई है।

उपभोक्ता केंद्रों में कीमतें चढ़ी हैं, जबकि उत्पादन केंद्रों में कारोबारियों को बढ़ते गैर-बिके स्टॉक का सामना करना पड़ रहा है। निर्यात पर दबाव की वजह से किसानों में अगले सीजन में इस फसल की कम खेती किए जाने की आशंका गहरा गई है। इससे कम फसल आपूर्ति की आशंका की वजह से इस सीजन में कीमतें चढ़ रही हैं।

ऊंची ढुलाई लागत और मजबूत बाजार मांग की वजह से बासमती की कीमतें 5 प्रतिशत तक चढ़ी हैं। मुंबई स्थित जिंस कारोबारी एवं निर्यातक देवेंद्र वोरा ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि सबसे ज्यादा बिकने वाली पूसा बासमती किस्म (पीबी1121) मौजूदा समय में 65 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रही है, जो 15 मार्च से 3-4 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि है। उन्होंने कहा, 'लॉकडाउन की घोषणा के बाद से बासमती की मांग बढ़ी है और तभी से इसकी कीमतें मजबूत हो रही हैं।' उन्होंने कहा कि बड़े कारोबारियों के पास बड़ी मात्रा में चावल स्टॉक बना हुआ है, क्योंकि उन्हें परिवहन संबंधी दिक्कतों की वजह से आपूर्ति की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

अमेरिका-ईरान गतिरोध और बाद में कोरोनावायरस की वजह से भारतीय बासमती निर्यातकों को दोहरा झटका लगा है, क्योंकि ईरान भारतीय बासमती के लिए प्रमुख बाजार है। भारत से बासमती निर्यात खेपों में ईरान का योगदान 33 प्रतिशत रहा है। इक्रा की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख निर्यात स्थानों में कोरोनावायरस के प्रसार से सामान की आवाजाही व्यवस्था ठप हो गई है जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है।

इसके अलावा, उद्योग का प्रदर्शन काफी हद तक निर्यात से जुड़ा हुआ है और उसे वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे घरेलू बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति की समस्या बढ़ सकती है और कीमतों में गिरावट आ सकती है। इक्रा की उपाध्यक्ष शीतल शरद ने कहा, '2017-2018 में 25 प्रतिशत और 2018-19 में 22 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज किए जाने के बाद बासमती निर्यात ईरान जैसे प्रमुख बाजारों से कम खरीदारी की वजह से 2019-20 में कमजोर पड़ा।'

निर्यात की वैल्यू 2018-19 के 4.37 अरब डॉलर से घटकर 2019-20 में 2.79 अरब डॉलर रह गई। कोविड-19 महामारी की वजह से 2019-20 की चौथी तिमाही में निर्यात में और कमी आने का अनुमान है।

व्यापार गोष्ठी

कोरोना संकट में कुछ राहत लेकिन और ज्यादा की जरूरत

कर्ज व कर में रियायत की दरकार

कोरोना संकट के कारण छोटे उद्योगों पर पड़ रहे प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा विशेष राहत दी जानी चाहिए। इसमें ऋण की सीमा में वृद्धि, कर छूट तथा आयकर व अन्य बकाया राशि जमा करने के लिए नियमों में राहत दी जाए। बैंकों के ब्याज दरों को भी घटाया जाए। पलायन कर चुके कामगारों की वापसी भी छोटे उद्योगों के लिए सुनिश्चित करायी जाए। उन स्थानों की इकाइयों को पहले शुरू किए जाएं, जहां कोरोना संदिग्ध कम हैं। श्रमिकों की संख्या में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने पर प्रबंधकीय समस्या कम होगी। जैसे कम लागत वाली वस्तुएं आयात की जाती हैं वैसे ही कम लागत वाली वस्तुएं अधिक उत्पादित कर इस अवसर का लाभ उठाया जा सकता है।

दीप्ति विश्वास
भोपाल, मध्य प्रदेश

जीएसटी में मिले छूट

कोरोना की मार से छोटे उद्योगों को बचाने के लिए ऋण दरों में कमी के साथ ही छोटे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती करनी चाहिए। ठप हो चुके उद्योगों को शुरू करने को प्राथमिकता मिले और अपने घरों लौट चुके संबंधित उद्योगों में काम करने वाले कामगारों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विशेष वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है। छोटे उद्योगों में उत्पादित सामग्री की मांग में वृद्धि के लिए आम जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने के उपाय भी करने होंगे। इसके लिए रिजर्व बैंक बाजार में तरलता बढ़ाने के विकल्पों पर विचार करे।

ऋत्विज तिवारी
पामगढ़, छत्तीसगढ़

चीन से आयात पर लगे प्रतिबंध

लॉकडाउन से छोटे उद्योगों की कमर टूट जाएगी और कुछेक पर तो अस्तित्व के खोने का भी खतरा मंडरा जाएगा। कोरोना की मार से छोटे उद्योगों को बचाने के लिए सरकार को इनके लिए विशेष पैकेज लाने की जरूरत है। छोटे उद्योगों के मजदूरों की वित्तीय मदद करनी चाहिए। ताकि इन मजदूरों को नुकसान न उठाना पड़े। लॉकडाउन के बाद भारत सरकार को चाहिए कि लंबे समय तक अब चीन के बाजार को देश में पूरी तरह पैर न पसारने दें, क्योंकि लॉकडाउन से पहले भी भारत में जब से चीनी सामान आना शुरू हुआ है, तब से न जाने भारत के कितने ही छोटे उद्योग या तो बंद हो गए हैं या उनपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

औपचारिकताओं को टाला जाए

कोरोना ने सभी व्यवसायिक गतिविधियों की कमर तोड़ दी है। हमें इस स्थिति से निपटना है तो सरकार को नई नीतियां बनानी होगी। अगर छोटे उद्योगों को बचाना है और व्यवसाय को प्रोत्साहित करना है तो कई तरह की औपचारिकताओं को अभी फिलहाल स्थगित करना होगा। व्यवसाय के लिए अच्छा माहौल बनाने तक सरकार, व्यवसायी, ग्राहक और अन्य को मिलजुलकर पुनर्स्थापित करने पर ही बात बन सकती है। फिलहाल मानव जीवन को बचाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए समय के साथ सब फिर से स्थापित हो जाएगा। मानव जीवन की रक्षा होने पर ही इन सब चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।

डॉ रसिकेश
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

लघु उद्योग को मिले सब्सिडी

कोरोना ने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। लघु उद्योगों का इससे प्रभावित होना लाजिमी है। छोटे उद्योगों को कोरोना की मार से बचाने के लिए कौशल आधारित क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही इनसे जुड़े लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए। लघु उद्योगों से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि को भी सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। छोटे उद्योगों द्वारा मुख्यत: दैनिक उपभोग वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है अत: इनका सुचारु रूप से कार्य करना अति आवश्यक है।

करनाराम
बाड़मेर, राजस्थान

श्रमिकों के वेतन में हो मदद

लॉकडाउन के कारण छोटे उद्योगों के सामने सबसे बड़ा संकट कर्ज की पुनर्भुगतान, ब्याज भुगतान और कर देने के साथ श्रमिकों को वेतन का भुगतान है। सरकार ने इन उद्योगों को संकट से उबारने के लिए कुछ राहत भरे उपाय किए हैं, लेकिन ये नाकाफी है। ऐसे में सरकार को छोटे उद्योगों की मदद के लिए श्रमिकों के वेतन का कुछ हिस्सा 4 महीने तक वहन करने, कर्ज पुनर्गठन के विकल्प के साथ साथ 6 महीने के लिए बकाया भुगतान पर रोक, स्वउद्यमी जैसे फेरी वाले, प्लंबर, बिजली मिस्त्री आदि को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण करने जैसे उपाय और करने चाहिए। सरकार को छोटे उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव की पड़ताल के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करनी चाहिए। सरकार को यह कदम उठाने चाहिए।

मनीष कुमार
दिल्ली

प्रोत्साहन की दरकार

कोरोना संकट की मार झेल रहे छोटे उद्योगों की क्षमता इतनी नहीं है कि वह लंबे समय तक संकट को झेल सकें। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि वह छोटे उद्योगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करें, जिसमें कर, वित्त संबंधी छूट शामिल हो। साथ ही आवश्यक वस्तु आधारित छोटे उद्योगों को हर संभव उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करें। जिससे उद्योगों के श्रमिकों को भी राहत मिलेगी। कुछ छोटे उद्योगों के उत्पादन प्रकृति में बदलाव लाया जाना चाहिए। कैरी बैग बनाने वाले उद्योग को मास्क तथा अल्कोहल आधारित उद्योग सैनिटाइजर का उत्पादन करना चाहिए। यह आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से लाभकारी होगा।

आयुष रंजन चौधरी
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

सरकारी नीतियों से बचेंगे उद्योग

वैश्विक महामारी कोविड-19 की मार वैसे तो प्रत्येक भारतीय व सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में पड़ रही हैं। लेकिन भारत के छोटे उद्योगों पर कोरोना की मार पड़ रही है। मध्यम उद्योग को कोरोना की मार से बचाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार दोनों को उनके पक्ष में ठोस नीति बनानी होगी। सरकार को नुकसान के भरपाई के लिए योजना बनानी चाहिए। छोटे उद्योग को बनाने में यदि किसी ने ऋण लिया हो तो सरकार को उन्हें कुछ समय देना चाहिए और देरी से किस्त भरने पर ब्याज नहीं लेना चाहिए। छोटे उद्योगों को ऋण की जरूरत पड़ने पर बैंक उन्हें ऋण अवश्य दे ताकि छोटे व्यापारी कोरोना की मार से बच सके।

कशिश वर्मा
दिल्ली

बकौल विश्लेषक

वेतन खर्च उठाए सरकार

कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा मार छोटे उद्योगों पर पड़ रही है। इन उद्योगों के लिए बिना कारोबार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य तय खर्चों आर्थिक बोझ सहना कठिन है। सरकार ने कुछ उद्योगों के लिए पीएफ जमा पर राहत दी है लेकिन यह नाकाफी है। सरकार को 70-80 फीसदी वेतन का भार खुद उठाने के साथ बिजली बिल में फिक्स चार्ज जैसे अन्य तय खर्चों पर राहत देनी चाहिए। बंदी के कारण भुगतान शृंखला अटक गई है। ऐसे में आगे बंदी समाप्त होने पर कार्यशील पूंजी का संकट पैदा हो सकता है। लॉकडाउन के बीच समाप्त हो रही है बैंक गारंटी का एमएसएमई सरकारी खरीद के संदर्भ में विस्तार हो और समय पर डिलिवरी के अभाव में कार्रवाई न हो। बड़े स्तर पर डिफॉल्ट से बचाने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट का भी विस्तार हो। एमएसएमई के लिए कैश क्रेडिट सीमा 20 फीसदी बढ़े। आरबीआई द्वारा घोषित राहत उपाय बैंकों के लिए अनिवार्य होने चाहिए।

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

अनिल भारद्वाज
महासचिव, फिस्मे

लॉकडाउन के बाद की रणनीति

भारत में 135 लाख से ज्यादा खुदरा कारोबारी हैं जो चार करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। कोरोना के चलते छोटे एवं मझोले उद्योगों पर काफी असर पड़ा है। पिछले 45 दिनों में खुदरा कारोबार घटकर 15 फीसदी पर आ गया है। रिटेलर्स एसोसिएशन के सर्वे के अनुसार 70 फीसदी खुदरा कारोबारियों का मानना है कि कारोबार को वापस सही स्थिति में आने में 6 माह से अधिक समय लग जाएगा। इसमें करीब 20 प्रतिशत नौकरियां जाने की भी बात सामने आई है। छोटे तथा मझोले कारोबारियों के लिए यह कठिन समय है और लॉकडाउन तथा कोरोनावायरस से उनके कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सरकार ने आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए कुछ राहत देने की कोशिश की है। हालांकि छोटे कारोबारियों को हालिया स्थिति से उबरने के लिए कई स्तरों पर काम करना होगा और लॉकडाउन के बाद काम करने की रणनीति बनानी होगी।

बातचीत : वीरेश्वर तोमर

कुमार राजगोपालन
मुख्य कार्याधिकारी, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

पुरस्कृत पत्र

जीएसटी व अन्य तय खर्चों में मिले राहत

रिजर्व बैंक ने कोरोना से बचाने के लिए छोटे उद्योगों को कुछ राहत दी है। लेकिन यह नाकाफी है। छोटे उद्योगों को कोरोना की मार से बचाने के लिए सरकार को छोटे उद्योगों को ब्याज, कर, बिजली बिल, वेतन जैसे तय खर्चों में राहत देने के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों के पास फंसे भुगतानों को जल्द जारी करने तथा बिना शर्त की सस्ती पूंजी मुहैया कराने जरूरत है।

बलराम साहू
बिलासपुर, छत्तीसगढ़

पुरस्कार राशि
500 रुपये

श्रेष्ठ पत्र

विशेष पैकेज मिले

रुबी सिंह
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाले एमएसएमई कोरोना की मार झेल रहे हैं। करीब 1.7 करोड़ छोटे उद्योगों के बंद होने का खतरा है। सबसे बड़ी चुनौती एमएसएमई के अप्रत्यक्ष या स्थायी रूप से जुड़े लोगों के लिए है। दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उद्यमियों को बिना काम के वेतन का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। सरकार को विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।

जीएसटी दरें घटें

गौतम एस आर
खंडवा, मध्य प्रदेश

कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से छोटे उद्योगों पर संकट के बादल छा गए हैं। वस्तुओं की आपूर्ति में आ रही मुश्किलों के साथ ही सरकारी और निजी कंपनियों की तरफ से भुगतान न मिलने जैसी मुश्किलों के कारण देश के छोटे उद्योगों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। ऐसे में सरकार द्वारा छोटे कारोबारियों से जुड़े सभी उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी आधा कर दिया जाए।

कर्ज में दें रियायत

डॉ हर्ष वर्द्धन
पटना, बिहार

कोरोना की मार से करीब 1.28 करोड़ छोटे उद्योगों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लगभग 35 करोड़ लोगों की आजीविका खतरे में है। कंपनियों को कर्मचारियों के वेतन और इंसेंटिव के भी लाले पड़े हैं। देश की 47 फीसदी कंपनियां करीब 25 फीसदी लोगों की छंटनी कर सकती हैं। सरकार को जीएसटी लगभग 2 वर्षों तक आधा करने और ऋण को खत्म करने चाहिए।

... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की इस बार का विषय है **लॉकडाउन में गांव-कृषि को कैसे बचाया जाए?**

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें: बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in

नई दिल्ली | 13 अप्रैल 2020 सोमवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

निजी अस्पतालों के वजूद पर संकट

छोटे अस्पताल बंद होने के कगार पर, बड़े अस्पतालों को भी कम से कम छह महीने चुनौतियों से जूझना होगा

सोहिनी दास और गिरीश बाबू

छोटे अस्पताल पीपीई किट की लागत ज्यादा होने की वजह से इसका इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं

- वित्त वर्ष की पहली छमाही में कम रहेंगे सर्जरी के मामले
- कोविड 19 की जांच और इलाज की लागत कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार खर्च वहन करे सरकार
- उद्योग ने तीन महीने तक बिजली के बिल माफ करने, जीएसटी में छूट देने और अस्पतालों की अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार से गुहार लगाई है
- छोटे अस्पतालों का दावा है कि उद्योग पहले ही करीब 10 फीसदी मार्जिन पर चलता है
- एक पीपीई किट की कीमत 1,800 रुपये है, छोटे अस्पताल इसका कम कर रहे इस्तेमाल

वाराणसी के आसपास एक अस्पताल समूह के प्रमुख एके कौशिक कहते हैं कि इस समय उनके लिए कर्मचारियों को वेतन देना ही मुश्किल हो रहा है। बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और पहले से निर्धारित ऑपरेशन के लिए मरीजों की आवक थम गई है। मरीज अस्पताल जाने से बचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

कौशिक ने कहा, 'वाराणसी, गोपीगंज और मिर्जापुर में मेरे तीन अस्पतालों में 600 कर्मचारी काम करते हैं। अब आमदनी में भारी कमी के कारण मेरे लिए उन्हें समय पर वेतन देना मुश्किल हो रहा है।' पूरे उद्योग में ओपीडी से इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (आईपीडी) में आने यानी भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 10 से 12 फीसदी है। अब ओपीडी में मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए मुश्किल से ही कोई मरीज भर्ती हो रहा है। निजी अस्पताल, विशेष रूप से छोटे अस्पतालों को अपने सामने वह संकट नजर आ रहा है, जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। विश्लेषकों का कहना है कि बड़ी अस्पताल शृंखलाओं को भी कारोबार सामान्य होने के लिए कम से कम छह महीने जूझना होगा।

एडलवाइस के विश्लेषक अंकित हातलकर ने कहा कि अस्पतालों पर यह असर अचानक पड़ा है। यह तब तक बना रहेगा, जब तक भारत में कोरोनावायरस के मामले नियंत्रण में नहीं आ जाते। उन्होंने कहा, 'यह असर कब तक रहेगा, इसका अनुमान लगाने का कोई सटीक तरीका नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अस्पतालों के लिए कारोबार सामान्य होने की उम्मीद अभी बहुत दूर है। पहले से तय की जाने वाली सर्जरी अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में सर्जरी के मामले अत्यंत कम रहने के आसार हैं और वित्त वर्ष 2021 में आमदनी कमजोर रहेगी।'

इसके अलावा अस्पताल कोविड-19 के मरीजों को संभालने के लिए अपने कर्मचारियों को तैयार नहीं कर पाए हैं, जिससे उन्हें परिचालन बंद करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी यह एक नमूना देखिए। पिछले 24 घंटे के दौरान मुंबई में कम से कम दो अस्पताल बंद हो गए क्योंकि उनके यहां मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। ये अस्पताल ताड़देव में भाटिया हॉस्पिटल और मुलुंड में स्पंदन हैं। उदाहरण के लिए स्पंदन में करीब 65 डॉक्टरों और नर्सों को क्वारंटीन में रखा गया है। मुंबई में वॉकहार्ट और जसलोक जैसे प्रमुख अस्पतालों को पहले ही सील कर दिया गया है, जबकि इन दोनों अस्पतालों को कोविड-19 के मरीजों के इलाज का केंद्र बनाया गया था।

एक निजी अस्पताल के मालिक ने नाम न प्रकाशित करने का आग्रह करते हुए बताया, 'अस्पतालों को सबसे पहले अपने कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) पर पैसा खर्च करने की जरूरत है, भले ही वे कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे हों या नहीं। इन किट की कीमत कम से कम 1,800 रुपये प्रति इकाई है। यही वजह है कि छोटे अस्पताल इन किट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ एक ही किट पूरे दिन पहन कर रहे हैं, जिसके दौरान वे विभिन्न मरीजों की जांच कर रहे हैं। यह आपदा को न्योता देना है।'

निजी अस्पताल इस संकट को पार करने के लिए सरकार से प्रोत्साहन पैकेज या अन्य किसी तरह की सहायता की मांग कर रहे हैं। अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या 50 फीसदी घट गई है, जबकि आपूर्ति पर लागत 10 से 30 फीसदी बढ़ गई है। हाल में अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप के वाइस-चेयरपर्सन प्रीता रेड्डी ने कहा, 'हमें बिजली, वेंटिलेटर और पूंजी खर्च जैसी बुनियादी लागतों पर प्रोत्साहन की दरकार है। उद्योग मिलकर सरकार से आग्रह करेगा क्योंकि हम एक तरफ मरीजों के इलाज को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दूसरी ओर अगर यह उद्योग निजी क्षेत्र के रूप में अपना वजूद नहीं बचा पाया तो चिकित्सा प्रणाली पूरी तरह बैठ जाएगी।'

इस समय कोविड-19 की जांच और इलाज सस्ता नहीं है। हालांकि जांच की कीमतें कम हुई हैं। अपोलो उम्मीद कर रही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार खर्च का एक निश्चित हिस्सा वहन करके जांच और इलाज की लागत को कम करें।

अस्पतालों के लिए वेतन, बिजली बिल, सालाना मरम्मत अनुबंध जैसे बहुत से तय खर्च हैं और ये किसी ठीकठाक अस्पताल के लिए कई करोड़ रुपये में होते हैं। एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (एएचपीआई) के तमिलनाडु चैप्टर के अध्यक्ष और मीनाक्षी मिशन हॉस्पिटल ऐंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन एस गुरुशंकर ने कहा कि पहले से तय होने वाली सर्जरी और ओपीडी के लिए मरीज नहीं आने से कोई आमदनी नहीं हो रही है और सभी निजी अस्पताल मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।

छोटे क्लीनिक और अस्पताल पहले ही बंद होने के कगार पर हैं। हालांकि गुरुशंकर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में यह उद्योग सरकार के साथ है, लेकिन उद्योग की समस्या का कोई समाधान खोजा जाना चाहिए। छोटे अस्पतालों का दावा है कि यह उद्योग पहले ही करीब 10 फीसदी मार्जिन पर चलता है।

गुरुशंकर ने कहा, 'इस महीने ज्यादातर छोटे क्लीनिक वेतन नहीं दे सकते और कर्मचारी पहले ही छोड़कर चले गए हैं। अप्रैल के अंत से ज्यादा बड़े अस्पतालों के पास कार्यशील पूंजी खत्म हो जाएगी और वे अपने खर्च पूरे करने की स्थिति में नहीं होंगे। यह बहुत खतरनाक स्थिति है क्योंकि कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे। ऐसा पहले ही कुछ अस्पतालों में हो रहा है। अगर अस्पतालों के पास कार्यशील पूंजी खत्म हो जाएगी तो यह बड़ी आफत होगी।' उद्योग ने मांग की है कि सरकार तीन महीने तक बिजली के बिल माफ करे, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में छूट दे और टैक्स एरियर जारी करे और अस्पतालों के अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। सरकार से यह भी कहा गया है कि वह वेंडरों से सुरक्षा साजोसामान दिलाने में मदद करे। ये वेंडर पहले ही सरकारी अस्पतालों को आपूर्ति कर रहे हैं।

कुछ छोटे अस्पतालों ने पहले ही अपने परिसर सरकार को मुफ्त में मुहैया कराए हैं, लेकिन बिना कर्मचारियों के। मुंबई के पूर्व उपनगर चेंबूर में जॉय हॉस्पिटल ने अपना पूरा परिसर वृहनमुंबई नगर पालिका को मुहैया कराया है, जो इसका इस्तेमाल करीब 45 मरीजों को रखने में कर रही है।

अस्पताल की मालिक दीप्ति जॉय पाटणकर ने कहा, 'हमने अपने परिसरों के इस्तेमाल के लिए कोई किराया नहीं मांगा है, लेकिन वे इस अवधि के दौरान बिजली-पानी के बिलों का भुगतान करेंगे। हमारे पास करीब 85 बेड की क्षमता है।'

गंभीर होते हालात

देश में कोरोना के 909 नए मामले, 31 की मौत

पिछले 24 घंटे में कोरोनावायरस के 909 मामले आए हैं और 31 लोगों की मौत हुई है। इस तरह देश में अब तक कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 8,447 हो गया है और मृतकों की संख्या 273 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि कोरोना के सक्रिय मामले 7,409 हैं क्योंकि 764 लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें छुट्टी दी जा चुकी है।

शनिवार शाम के बाद 31 मौत हुई हैं। इनमें मध्य प्रदेश में तीन, महाराष्ट्र में 17, दिल्ली में पांच, गुजरात में तीन, तमिलनाडु में दो और उत्तर प्रदेश में एक मौत हुई है। अब तक कुल 273 मौतों में महाराष्ट्र 127 मौतों के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 36, गुजरात में 22, दिल्ली में 19, पंजाब में 11, तेलंगाना में नौ और तमिलनाडु में 10 लोगों की मौत हुई है।

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक सबसे अधिक संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में 1,761 आए हैं। इसके बाद दिल्ली में 1,069, तमिलनाडु में 969, राजस्थान में 700, तेलंगाना में 504 और मध्य प्रदेश में 564 मामले आ चुके हैं। वहीं संक्रमण के मामले उत्तर प्रदेश में 452, आंध्र प्रदेश में 381, केरल में 374 और गुजरात में 432 हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि अगर कोरोनावायरस के मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होती है तो सरकार 'अतिरिक्त तैयार' है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि सरकार सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 की जांच क्षमता बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि चीन, जापान और कोरिया में फिर से कोरोनावायरस के मामले बढ़ना चिंता का विषय है उन्होंने सामाजिक दूरी पर जोर देते हुए इसे इस घातक वायरस की 'सामाजिक वैक्सीन' करार दिया।

उन्होंने सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में कहा कि सबसे अधिक जोर प्राथमिक चिकित्सा बुनियादी ढांचे की क्षमता को बढ़ाने पर दिया जा रहा है, जिनमें विशेष अस्पताल, आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड और क्वारंटीन सुविधाएं आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'कोविड-19 के मरीजों के लिए विशेष अस्पतालों की स्थापना बढ़ाई जा रही है। इन प्रयासों में सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पताल, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, सैन्य अस्पताल और भारतीय रेलवे योगदान दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड ने विशेष टेंट तैयार किए हैं ताकि दूर के इलाकों में चिकित्सा बुनियादी ढांचा बढ़ाया जा सके। *एजेंसियां*

चिकित्सकों को रहने की सुविधा दे रहीं होटल कंपनियां

समरीन अहमद

राजस्थान के कोटा में सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोरोनावायरस रोगियों का इलाज करने वाले सौरभ चित्तौड़ा शाम 5:30 बजे तक की शिफ्ट कर लेते हैं। इसके बाद वह अपने अस्थायी घर की ओर रवाना होते हैं जहां वह सबसे पहले भोजन करते हैं क्योंकि काम के चलते उन्हें दोपहर का भोजन करने का समय नहीं मिल पाता।

सौरभ कहते हैं, 'इस समय मैं कोविड-19 से ग्रसित 134 मरीजों का इलाज कर रहा हूं। मेरे घर में 65 वर्ष से अधिक उम्र के मेरे माता पिता हैं। मेरे बच्चों की उम्र भी 5 साल से कम है। इसलिए अब मैं अस्थायी तौर पर एक को-लिविंग जगह पर रहने के लिए आ गया हूं।' एक ही शहर में रहने के बाद भी सौरभ पिछले 10 दिनों से अपने परिवार से नहीं मिले हैं।

डॉ. चित्तौड़ा कोटा में 'हेलो वर्ल्ड' द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे एक को-लिविंग क्षेत्र में रह रहे हैं। कंपनी ने कोटा की अपनी 2 परिसंपत्तियों को इस कार्य में लगा दिया है जिसमें से एक जगह स्वास्थ्य कर्मी रह रहे हैं तो वहीं दूसरी जगह 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते शहर में फंसे प्रवासियों के लिए है।

हेलो वर्ल्ड के संस्थापक जितेंद्र जगदेव कहते हैं, 'हमने कोटा, जयपुर तथा एनसीआर क्षेत्र की अपनी पांच संपत्तियां

सुविधाएं दे रहे को-लिविंग स्टार्टअप

कोविड-19 मरीजों तथा लॉकडाउन के चलते फंसे लोगों की सेवा कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खोल दी हैं।' हेलो वर्ल्ड एक को-लिविंग स्टार्टप है जिसे टाइगर ग्लोबल से वित्त पोषण मिला है।

अभी तक कंपनी ने इन संपत्तियों में चिकित्सकों, नर्सों और वार्ड बॉय के लिए 150 बिस्तर तैयार किए हैं। स्वास्थ्य पेशेवरों को दिन में किसी भी समय भोजन उपलब्ध कराने के लिए यहां 24 घंटे हाउसकीपिंग की सुविधा उपलब्ध है। जगदेव कहते हैं, 'कुल मिलाकर मुंबई और बेंगलूरु सहित सभी शहरों में इस महीने के पहले चरण में कुल मिलाकर 500 बिस्तर तैयार कर रहे हैं।

हेलो वर्ल्ड लॉकडाउन के चलते बंद पड़े स्कूलों से भी बात कर रही है, जिससे इन इमारतों को प्रवासी मजदूरों के लिए अस्थायी घरों में परिवर्तित किया जा सके। जगदेव कहते हैं, 'हम अगले 3 महीनों तक अपनी सेवाएं मुफ्त में देंगे जिसमें खाद्य सेवा भी शामिल है। हम बाह्य माध्यमों से वित्त जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।' एक अन्य को-लिविंग स्टार्टअप गैस्चर ने मल्टी स्पेश्यलिटी हॉस्पिटल नारायण हेल्थ के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अपनी खाली परिसंपत्तियों को देने के लिए बात की हैं। हालांकि फिलहाल अस्पताल ने इस तरह के किसी आश्रय या स्थान की मांग नहीं की है। गैस्चर के संस्थापक श्रीराम चित्तूरी कहते हैं, 'निर्माण कार्यों में लगे जो श्रमिक लॉकडाउन के दौरान विभिन्न साइटों पर फंस गए हैं, वे सभी कंपनी द्वारा प्रदान किए गए क्वार्टरों में सुरक्षित रह रहे हैं। गेस्चर की मूल कंपनी शैंडर्स, भोजन, चिकित्सा सहायता आदि का ध्यान रख रही है।'

भीषण संकट झेल रहा घरेलू वाहन उद्योग

पृष्ठ 1 का शेष

कसान में पवन जैसे कई अस्थायी कामगार रहते हैं। पवन कुछ उन गिने चुने लोगों में शामिल हैं, जिनका रोजगार बरकरार है। बाकी ज्यादातर दूसरे लोगों के लिए उत्पादन संयंत्र अधिक दिनों तक बंद रहने का साफ मतलब है कि उनका भविष्य डांवाडोल है। मारुति सुजूकी में कार्यकारी बोर्ड के सदस्य, मानव संसाधन, राजेश उप्पल कहते हैं,'कर्मचारियों को समय पर दिया जा रहा है। विभिन्न स्थापित माध्यमों के जरिये सभी नियमित एवं बाहर से रखे गए कर्मचारियों के साथ संवाद हो रहा है। हम लॉकडाउन के बीच कर्मचारियों के परिवारों को ढाढस देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं।'

हालांकि इस वाहन उत्पादन क्षेत्र में बड़ी संख्या में छोटे एवं मझोले कल-पुर्जे विनिर्माता अस्तित्व बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वाहन उद्योग पिछले कई दशकों का सबसे भीषण संकट झेल रहा है और कई छोटी कल-पुर्जा विनिर्माता कंपनियां बेहद नाजुक दौर से गुजर रही हैं। कल-पुर्जा उद्योग को लगता है कि कोविड-19 संकट गहराने और हालात बिगड़ने से गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। जापानी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल को स्प्रिंग की आपूर्ति करने वाली कंपनी में काम करने वाले राकेश इसका एक उदारहण हैं। 25 मार्च को लॉकडाउन के पहले दिन 34 वर्षीय राकेश ने अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बिजनौर लौटने का निर्णय लिया। हालांकि जब वे आनंद विहार बस अड्डा पहुंचे तो वहां पहले से ही 20,000 लोग वहां खड़ीं कुछ बसों में सवार होने के लिए मौजूद थे। हार कर उन्हें लौटना पड़ा। राकेश को पिछले दो महीने से अधिक समय समय तक काम करने का भत्ता भी नहीं मिला है। राकेश और उनका परिवार इस समय एक सामुदायिक रसोई से मिलने वाले भोजन पर दिन गुजार रहे हैं।

ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जैन का कहना है कि ज्यादातर कंपनियां कामगारों को नौकरी से निकालने की हिमाकत नहीं की है और मार्च का वेतन समय पर दिया है।

बीएस बातचीत

सामूहिक प्रतिरोधकता से ही कोरोनावायरस पर होगा काबू

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर के पूर्व प्रिंसिपल **डॉ जयप्रकाश मुलिइल** देश के अग्रणी महामारी-विशेषज्ञों में से एक हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ कई सलाहकार समितियों में शामिल रहे मुलिइल ने संक्रामक बीमारियों के क्षेत्र में लंबा काम किया है। उन्होंने **सोमेश झा** के साथ कोविड-19 महामारी के प्रसार एवं नियंत्रण पर लंबी बातचीत की। पेश हैं संपादित अंश:

छायांकन : बिनय सिन्हा

लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार राज्यों से एक निकासी रणनीति बनाने को कह रही है। हमें दूसरे चरण में किस तरह जाना चाहिए?

पूरी रणनीति इस सोच पर आधारित है कि संक्रमित लोगों की तलाश कर और उन्हें अलग-थलग रखकर हम महामारी पर काबू नहीं कर पाएंगे। यानी वायरस पर काबू पाने का सवाल ही नहीं है। फिर हमारे पास यही रास्ता बचता है कि संक्रमण होने पर हम उन लोगों की देखभाल करेंगे। लेकिन ऐसी सोच थोड़ी असहज करती है क्योंकि वायरस का प्रसार काफी तीव्र गति से हो रहा है लिहाजा हम अस्पतालों में आने वाले संक्रमित लोगों की बड़ी संख्या का इलाज पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें यह देखना होगा कि इस समस्या पर काबू पाने का क्या कोई और रास्ता है? वर्ष 2009 में फैला एच1एन1 इन्फ्लूएंजा 2-3 महीनों तक रहने के बाद अपने-आप ही गायब हो गया था। इसकी वजह यह थी कि वायरस को लेकर लोगों के बीच एक सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी। इस तरह हमारे पास अकेला विकल्प यही है कि समय के साथ कोरोनावायरस को लेकर भी एक तरह की सामूहिक प्रतिरोधकता विकसित हो जाए। लेकिन हमें यह नहीं पता है कि उस स्तर तक पहुंचने के पहले आबादी का कितना हिस्सा संक्रमण की चपेट में आ चुका होगा। उसके बाद तो जादुई ढंग से सब कुछ नीचे आने लगेगा।

अगर संक्रमित होने वाली आबादी का अनुपात 50-60 फीसदी रहता है तो उसमें से कितने लोग मर जाएंगे। वह संख्या स्वीकार्य नहीं हो सकती। इस बीमारी के बारे में एक खास बात यह है कि कम उम्र के लोगों में यह अधिक असर नहीं डालती है जबकि 60 साल से ऊपर के लोगों में मृत्यु दर अधिक है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि उसकी आबादी के केवल 12.5 फीसदी लोग ही 55 साल से अधिक उम्र के हैं। इस तरह अगर हम इन उम्रदराज लोगों का ध्यान रखें और उनसे कम उम्र के लोगों में इसे धीमी गति से फैलने भी दें तो यह तरीका काम कर सकता है। बस भीड़-भाड़ से बचें, एक-दूसरे से दूरी बनाकर रहें। उद्योग को फिर से चालू करना है और कृषि कार्य भी करने हैं। उसी के साथ युवा लोग संक्रमण से मुक्त होते जाएंगे। जब सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता एक खास स्तर तक पहुंच जाएगी तो यह माना जा सकता है कि महामारी पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आने वाले समय में यह दोबारा आ सकती है लेकिन तब तक हमारे पास वैक्सीन आ चुकी होगी।

सरकार के लिए सामूहिक प्रतिरोधकता पर दांव लगाना कितना सही है?

हमारे पास इसके सिवाय रास्ता क्या है? कोई सुझाव हो तो बताएं।

दक्षिण कोरिया जैसे देश बड़े पैमाने पर टेस्ट कर रहे हैं...

कोविड-19 के एक टेस्ट का खर्च 4,500 रुपये है और यह टेस्ट स्वस्थ-अस्वस्थ हर किसी का होना है। भारत के 1.30 अरब लोगों का टेस्ट कर पाना संभव है क्या? अगर आप टेस्टिंग बढ़ा देते हैं तब भी बीमारी रहने वाली है। इनमें से अधिकांश मामले सब-क्लिनिकल हैं।

ब्रिटेन ने सामूहिक प्रतिरोधकता आजमाने की कोशिश की लेकिन इसमें कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। आपकी क्या राय है?

जिस जगह पर आवाजाही अधिक रहेगी, वहां संक्रमण उतनी ही तेजी से फैलेगा। जब भी कोई नया वायरस आता है तो लोगों में उससे लड़ने की क्षमता कम होती है और यह एक से दूसरे इंसान में फैलता जाता है। लेकिन एक स्तर पर पहुंचने के बाद उसका प्रसार थम जाता है। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को धीमा रखना होगा ताकि अधिक संक्रमित लोगों की देखभाल का इंतजाम किया जा सके। ब्रिटेन ने यह काम नहीं किया।

लेकिन जगह की कमी वाले भारत में क्या बुजुर्गों को युवा आबादी से सुरक्षित रख पाना मुमकिन होगा?

हमें बुजुर्गों को दो मीटर दूर ही रखने की जरूरत है जिसके लिए अलग कमरा काफी होगा। सामाजिक भेदभाव नहीं बल्कि भौतिक दूरी की जरूरत है। हालांकि तब भी बुजुर्गों के संक्रमित होने की आशंका रहेगी लेकिन प्रसार को रोका जा सकेगा।

देश भर में लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमें क्या करना चाहिए?

लॉकडाउन हटने के बाद मामले बढ़ेंगे। हमें उन लोगों का ध्यान रखना होगा। अगर वेंटिलेटर नहीं हैं तो ऑक्सीजन के जरिये कुछ राहत दी जा सकती है। हमारी स्वास्थ्य प्रणाली अमेरिका जितनी आधुनिक नहीं है। अगर उन्हें दिक्कत हो रही है तो हमें कितनी मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि इस बीमारी का डर हमें ज्यादा सता रहा है। अपना, अपने परिवार और अपने माचा-पिता का ध्यान रखिए और किसी के बहुत करीब न जाएं।

आप लॉकडाउन खत्म कर सब कुछ पहले जैसा करने की सलाह दे रहे हैं?

मैंने आपको एक ढांचा बताया है। अब यह फैसला करना है कि बसों में कितनी भीड़ हो सकती है और क्या क्रिकेट मैच खेले जा सकते हैं? अगर हम सामान्य जीवनशैली की तरफ लौटते हैं तो आप संक्रमणों की भरमार नहीं झेल सकते हैं। इस प्रक्रिया को धीमा करने की जरूरत है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि संक्रमण का दौर जारी रहेगा लिहाजा सामुदायिक प्रतिरोधकता की तरफ बढ़ना होगा।